संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050
Postal Reg.No.-13/Surguja DN/2023-2025

दैनिक घटती घटना

Www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अम्बिकापुर,वर्ष 20,अंक -132 बुधवार , 13 मार्च 2024 , पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये

संक्षिप्त खबर

भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश

नई दिल्ली,12 मार्च 2024(ए)। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया।. हादसा जैसलमेर के जवाहर नगर में हुआ। हालांकि, इस हादसे में पायलट सुरक्षित बचने में कामयाब रहा। पायलट ने सही समय पर खुद को प्लेन से इजेक्ट कर लिया।. क्रैश होने वाला भारतीय सेना का एयरक्राफ्ट एलसीए यानी की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस था। एयरक्राफ्ट हादसे के वक्त ऑपरेशनल ट्रेनिंग पर था। हादसे के बाद सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है।

एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को भेजा

» ईडी 15 मार्च तक वेबसाइट पर अपलोड करेगा...

» सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेडलाइन दी थी...

नई दिल्ली,12 मार्च 2024 (ए)। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5.30 बजे सौंप दिया। बार एंड बेंच ने एक्स पर ये जानकारी दी। चुनाव आयोग इस पूरे डेटा को 15 मार्च तक अपलोड कर देगा।

चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदी को भी सार्वजनिक करेगा,जो अब तक केवल सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और 12 मार्च शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था।वहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि सरकार राष्ट्रपति के जरिए कानूनी राय हासिल करे और तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हो।

सीजेआई ने एसबीआई से पूछा था- 26 दिन में आपने क्या किया?

इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआईकी याचिका पर सोमवार (11 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट सुनवाई की थी। एसबीआईने कोर्ट से कहा था- बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा- पिछली सुनवाई (15 फरवरी) से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया?

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा- एसबीआई12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था।

4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी।

2 याचिकाएं और दोनों पक्षों की सुप्रीम कोर्ट में दलील

एसबीआई की अपील - जानकारी जुटाने के लिए और वक्त चाहिए- कोर्ट ने सीबीआईको 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी देने का निर्देश दिया था। लेकिन 4 मार्च को ही एसबीआईने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जिसमें कहा कि राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। एसबीआई ने कहा कि उन्हें डिटेल निकालने के लिए और समय चाहिए।

एडीआर की आपत्ति - एसबीआई के पास बॉन्ड का यूनीक नंबर, फिर देर क्यों- एडीआर ने 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी।एडीआर ने कहा कि एसबीआई का मोहलत मांगना इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। एसबीआई का आईटी सिस्टम इसे आसानी से मैनेज कर सकता है। हर बॉन्ड में एक यूनीक नंबर होता है। इसके जरिए रिपोर्ट तैयार कर इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती है।

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी

43 उम्मीदवारों के नाम का एलान

नई दिल्ली,12 मार्च 2024(ए)। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें चार राज्यों के 43 उम्मीदवारों के नाम का एलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस सूची पर मुहर लगाई गई।

दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य सदस्य शामिल हुए थे। इससे पहले सीईसी की पहली बैठक सात मार्च को हुई थी और आठ मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों का एलान हुआ था।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। नकुल नाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। राहुल कासवा राजस्थान के चुरू से चुनाव लड़ेंगे। वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे।

इससे पहले सीईसी की पहली बैठक सात मार्च को हुई थी और आठ मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों का एलान हुआ था।

कमलनाथ और अशोक गहलोत के बेटे को मिला टिकट

निर्वाचन आयोग कभी भी आगामी आम चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब कांग्रेस ने अपने लोकसभा कांग्रेस ने इस लिस्ट में 7 जनरल, 13 ओबीसी,10 एससी, 9 एसटी और एक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है।. इस लिस्ट में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है.। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट दिया है तो बीजेपी के कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्वां को चूरू लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा इस लिस्ट में जोरहाट से गौरव गोगोई, सिलचर से सुरज्या खान, जालोर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को अपना प्रत्याशी बनाया है।

नायब सैनी ने ली हरियाणा सीएम पद की शपथ

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा

चंडीगढ़,12 मार्च 2024 (ए)। हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ। नायब सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस शपथ समारोह में दिलचस्प यह है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी के चार विधायक मौजूद रहे। यह चौटाला के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के साथ सूबे के अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बड़ा फेरबदल हुआ. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पद से इस्तीफा दे दिया है. निर्दलीय विधायक बीजेपी के समर्थन में आगे आए हैं. इसके साथ ही बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटना तय है. कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेदों की वजह से ये गठबंधन टूट रहा है.

खट्टर के बाद हिमंत विश्व सरमा ने कही इस्तीफा देने की बात

हिमंत विश्व सरमा ने इस्तीफे की बात मचा बवाल

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद हिमंत विश्व सरमा ने इस्तीफा देने की बात कहकर तहलका मचा दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि अगर राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए आवेदन नहीं करने वाले किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो वह इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे।

यूपी के 5 नए मंत्रियों को मिला विभाग

लखनऊ,12 मार्च 2024 (ए)। उत्तर प्रदेश में नए मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए है। जिसमें दारा सिंह को कारागार विभाग, ओपी राजभर को पंचायती राज एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। योगी सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का मंगलवार को बंटवारा कर दिया गया। नए मंत्रियों में ओमप्रकाश राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, हज व मुस्लिम वक्फ विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं दारा सिंह चौहान कारागार विभाग संभालेंगे। पहली बार मंत्री बने सुनील शर्मा को सूचना

प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अनिल कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। वहीं योगी मंत्रिमंडल के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति अब नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री बनाये गए हैं।

बता दें कि पांच मार्च को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें ओमप्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा व अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील कुमार शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली थी।

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा सीएए पर रोक लगाने की मांग

नई दिल्ली,12 मार्च 2024 (ए)। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में, आयूएमल ने कहा कि नागरिकता संशोधन नियम, 2024 मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के पक्ष में अनुचित लाभ पैदा करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।इसमें कहा गया है कि सीएए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 250 याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं और यदि सीएए को असंवैधानिक माना जाता है, तो एक असामान्य स्थिति उत्पन्न होगी। जिन लोगों को लागू अधिनियम और नियमों के तहत नागरिकता मिल गई होगी, उनकी नागरिकता छीननी होगी।इसलिए, सीएए और लागू नियमों के कार्यान्वयन को तब तक के लिए स्थगित करना, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में है, जब तक कि न्यायालय मामले का फैसला नहीं कर देता।

खड़गे को लेकर कांग्रेस पार्टी में बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली,12 मार्च 2024 (ए)। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस साल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

अब ऐसी खबरों के आने से कांग्रेसी खेमें में टेंशन बढ़ चली है। दरअसल, पिछले हफ्ते कर्नाटक के प्रत्याशियों की सूची को लेकर हुई बैठक में सभी ने गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से खरगे के नाम पर सहमति जताई है लेकिन सूत्रों से जानकारी आ रही है कि वो इस सीट से अपने दामाद राधाकृष्णन डोड्डामणि को उतार सकते हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे गुलबर्गा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार जीते थे लेकिन 2019 में वह हार गए थे। तब से वह राज्यसभा में हैं, जहां वह विपक्ष के नेता हैं और उच्च सदन में उनके चार साल और बचे हैं। मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। खबरों की मानें तो वह भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। खरगे का कहना है कि वह फिलहाल पूरे देश पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

किसे क्या दी गयी जिम्मेदारी

रायपुर,12 मार्च 2024(ए)। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है। इसमें एक जिले के कलेक्टर को बदला गया है। आईएएस अमृत विकास तोपनो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है।वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है।राज्य शासन ने आईएएस अन्बलगन पी सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।आईएएस दीपक सोनी पंजीयक, सहकारी समिति तथा अतिरिक्त प्रभार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन को केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए आयुक्त मनरेगा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दीपक सोनी द्वारा आयुक्त मनरेगा का कार्यभार ग्रहण करने पर निहारिका बारिक भाप्रसे (1997) प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त, मनरेगा केवल आयुक्त, मनरेगा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी। आईएएस कुलदीप शर्मा भाप्रसे (2014) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ नियंत्रक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अमृत विकास तोपनो भाप्रसे (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सक्ती के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं आईएएस नुपूर राशि पन्ना कलेक्टर, जिला-सक्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के पद पर पदस्थ किया गया है।नुपूर राशि पन्ना, भाप्रसे द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया गया है। वहीं नम्रता जैन, भाप्रसे (2019), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर पदस्थ किया गया है।

काला जठेड़ी और लेडी डॉन:अनुराधा चौधरी की हुई शादी

सुरक्षा के लिए पुलिस अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखी

नई दिल्ली,12 मार्च 2024 (ए)। गैंगस्टर काला जठेड़ी और रिवॉल्वर रानी के नाम से कुख्यात अनुराधा चौधरी की शादी हो गई है। गैंगस्टर संग लेडी डॉन की यह शादी बेहद ही कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है। शादी के दौरान मैडम मिंज उर्फ अनुराधा चौधरी सुर्ख लाल जोड़े में नजर आई। वही काला जठेड़ी ने कुर्ता-पायजामा पहन रखा था। गैंगस्टर काला जठेड़ी के सिर पर लाल पगड़ी भी नजर आई। लेडी डॉन संग गैंगस्टर की शादी के दौरान काफी कुछ खास रहा। शादी में पुलिस ने डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डीजे वालों को पुलिस टीम ने विवाह स्थल पर जाने ही नहीं दिया और उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। इस शादी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और हिस्ट्रीशीटर अनुराधा चौधरी की शादी के दौरान पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। संदीप अभी तिहाड़ जेल में बंद है और दिल्ली की एक अदालत ने उसे शादी के लिए पैरोल दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से सीधे विवाह स्थल पर पहुंचा था और उसके साथ भारी पुलिस बल की तैनाती थी। यहां आने के बाद उसने कुछ वक्त तक अपनी होने वाली पत्नी अनुराधा चौधरी के साथ बातचीत की और फिर दोनों सीधे

शादी के मंडप में पहुंचे थे। यहां काला जठेड़ी ने लेडी डॉन को सिंदूर भी लगाया। सूत्रों के मुताबिक,एसडब्ल्यूएटी दिल्ली पुलिस की टीम, थर्ड बटालियन, स्पेशल स्टाफ और करीब 150-200 पुलिसवालों की टीम विवाह स्थल पर तैनात की गई थी। यह विवाह द्वारका के एक बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुआ है। पुलिस ने शादी में आने वाले मेहमानों की पूरी लिस्ट की स्क्रूटनी भी की थी। एक गैंगस्टर की शादी के लिए पैरोल मांगते वक्त उसके वकील रोहित दलाल ने दलील दी थी कि कानून में शादी का अधिकार की व्याख्या की गई है। यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है। याचिकाकर्ता और उसकी मंगेतर दोनों ही व्यस्क हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी शादी के लिए अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज खुद स्कॉर्पियो चलाकर दिल्ली पहुंची थी। इस शादी में अनुराधा के परिवार से जुड़े कुछ लोग भी मौजूद थे। बता दें कि काला जठेड़ी कई गंभीर अपराधों में जेल में बंद है। उसपर मकोका भी लगाया गया है। काला जठेड़ी पर क्राइम सिंडिकेट चलाने का इल्जाम है। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी दोनों को ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। अनुराधा काला जठेड़ी गैंग की ही सदस्या है। वो मारे गए एक अन्य गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की करीबी रही है। अनुराधा चौधरी पर रंगदारी, किडनैपिंग, हत्या समेत कई अन्य केस राजस्थान और दिल्ली में दर्ज हैं। अनुराधा चौधरी इस वक्त जमानत पर है।

श्रीनगर में मोदी ने बताई सच्चाई

संपादकीय

कहने की जरूरत पड़ी

टिप्पणियां साधारण इस लिहाज से हैं कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में- जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो- इन्हें कहने की जरूरत नहीं पडऩी चाहिए। मगर आज हालात ऐसे हैं कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते दो साधारण बातें कहीं, लेकिन वो अखबारों में प्रमुख सुर्खियां बनीं। ये टिप्पणियां साधारण इस लिहाज से हैं कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में- जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो- इन्हें कहने की जरूरत नहीं पडऩी चाहिए। मगर आज देश के हालात ऐसे हैं कि ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और अंततः कोर्ट को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करनी पड़ती है। पहली टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने की आलोचना से संबंधित थी। एक प्रोफेसर ने इस कदम की आलोचना की थी।उन्होंने कहा था कि जिस रोज ये कदम कदम उठाया गया, वह एक काला दिन था। दूसरी टिप्पणी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर उसे बधाई दिए जाने से संबंधित थी। कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के पीछे दुर्भावना की तलाश नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा- हर भारतीय नागरिक को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने की आलोचना करने का अधिकार है। जिस रोज ये अनुच्छेद रद्द किया गया, उसे काला दिन बताना प्रतिरोध की भावना और रोष की अभिव्यक्ति है।अगर राज्य की हर आलोचना या प्रतिरोध को धारा 153-ए के तहत अपराध ठहराया जाएगा, तो लोकतंत्र- जो संविधान की अनिवार्य विशेषता है- टिक नहीं पाएगा।' कोर्ट ने अपनी दूसरी टिप्पणी में कहा कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कोई भारतीय नागरिक शुभकामना देता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यह सद्भावना का इजहार है।

संविधान के अनुच्छेद 370 की जद से जम्मू-कश्मीर को बाहर किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 7 मार्च को पहली बार कश्मीर घाटी पहुंचे। प्रधानमंत्री बतौर दूसरी पारी में यह उनकी पहली कश्मीर यात्रा थी। दूसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद उनकी सरकार ने उस संवैधानिक प्रावधान को जम्मू-कश्मीर से हटाने की कवायद शुरू कर दी थी, जो राज्य को पीछे धकेल रहा था, उसकी प्रगति की राह में रोड़ा था।गत 7 मार्च को पहली बार उन्होंने कश्मीर से हमें यह याद दिलाया कि अनुच्छेद 370 कश्मीर का गला घोंट रहा था। अगर राजनैतिक नज़रिए से देखा जाए तो यह याद दिलाने की लिए कश्मीर से बेहतर जगह कौन-सी हो सकती थी? यह एक महत्वपूर्ण यात्रा थी जिसमें मोदी ने कई सन्देश दिए, जुमलेबाजी भी की और अपने राजनैतिक कौशल का प्रदर्शन भी किया। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि जो नैरेटिव वे बुनते हैं, उससे ज़रा भी इधर-उधर नहीं होते।कश्मीर को हमेशा से दुहा और बेचा जाता रहा है ङ्क राजनैतिक सन्दर्भ में, सामाजिक सन्दर्भ में, भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से, धर्म और पहचान की नाम पर और अपनी-अपनी आपबीती के ज़रिये। वहां के रहवासियों ङ्क मुसलमानों और पंडितों दोनों ने उसे बेचा, अपने-अपने नैरेटिव के ज़रिये।और दोनों के नैरेटिव में दर्द है और दोनों के नैरेटिव दिल दहलाने वाले हैं। फिर कलाकारों, फोटोग्राफरों और फिल्म निर्माताओं ने कश्मीर को बेचा। उसकी कुदरती खूबसूरती और खूनखराबा, वहां की हसीन वादियाँ और हवा में तैरता डर, शांत माहौल को चीरती आहें और गुस्सा ङ्क इन सबको अगणित बार दुहा और बेचा गया।अनुच्छेद 370 और 35ए के विशेष प्रावधानों से कश्मीरियों को कोई विशेष लाभ नहीं मिला ङ्क न आज़ादी, न गौरव, न स्वायत्ता और ना शांति और ना ही किसी लाभ की गारंटी। कश्मीर को बेच कर सबने फायदा कमाया और सबसे बड़े लाभार्थी थे राजनेता। जब राजनीति बांटने लगती है, ज़हर फैलाने लगती है तब सबसे ज्यादा कष्ट भोगते हैं आम लोग।कश्मीर और उसके लोगों ङ्क विशेषकर उन मुसलमानों, हिन्दुओं, सिक्खों और ईसाईयों ने जो अपने घर छोड़ कर नहीं गए और जो उथलपुथल और नीरवता दोनों को झेलते हुए वहीं रहे आए ङ्क ने बहुत कुछ भोगा है और बहुत लम्बे समय तक भोगा है। शांति के दिन छोटे और कम रहे और गड़बड़ियों और बेचैनी के रातें लम्बी और ज्यादा रहीं। बल्कि बेचैनी, असंतोष और गुस्सा कश्मीर की पहचान बन गए।सन 2019 के चुनाव में भी कश्मीर को एक राजनैतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया गया। कश्मीर पर लिखा गया, कश्मीर पर बोला गया, कश्मीर पर फिल्में बनीं। इन सबमें जो नैरेटिव बनाए गए उनमें भी और राजनैतिक प्रचार में भी, हिंसा छाई रही। और हिंसा ही कश्मीर का नैरेटिव बन गई। कश्मीर विलाप और विषाद की घाटी बन गई।मगर 5 अगस्त, 2019 को इस सब पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। नतीजा यह कि कईयों के लिए नरेन्द्र मोदी एक

ऐसे व्यक्ति बन गए जो निर्णय लेना जानते है और जो निर्णय लेते है। वे एक तानाशाह नेता लगते हैं, उनके व्यवहार में दादागिरी का पुट है, नीतियों के निर्माण और उन पर अमल का उनका तरीका गैर-प्रजातान्त्रिक प्रतीत होता है और आने वाली पीढ़ियों को कदाचित उनकी विरासत उतनी शानदार नहीं लगेगी जितनी हमें अभी लगती है।लेकिन कश्मीर के मामले में उन्होंने जो किया उसके लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे और 370 एक ऐसा अंक होगा जो भुलाया नहीं जा सकेगा। कश्मीर की बेड़ियाँ काट दी गई हैं। दर्द और दहशत के नैरेटिव के सौदागरों को नये नैरेटिव ढूँढने पड़ रहे हैं। इनमें अब प्रजातंत्र के अभाव का मसला जुड़ गया है।सन 2019 के बाद कश्मीर की मोदी की इस पहली यात्रा के राजनैतिक निहितार्थ भी हैं। आम चुनाव के पहले मोदी ने बख्शी स्टेडियम के मंच से अपना नैरेटिव देश के सामने पेश किया। वसंत की उस सुबह हवा में ठंडक तो थी मगर आसमान साफ़ था और धूप भली लग रही थी। प्रधानमंत्री ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा की लिए 370 केवल एक नंबर नहीं है बल्कि एक गंभीर सोच का प्रतीक है।वे उस नैरेटिव से ज़रा भी इधर-उधर नहीं हुए, जो नैरेटिव उन्हें ताकत देता है। चुनाव की पूर्वसंध्या पर कश्मीर के दिल से उन्होंने दरअसल कश्मीर को नहीं बल्कि भारत को संबोधित किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में उन्होंने कश्मीर के बारे में एक ऐतिहसिक और साहसिक कदम उठाया था। उन्होंने भारत को उन दीवारों की याद दिलाई जो कश्मीर और शेष भारत के बीच तामीर कर दी गईं थीं। उन्होंने कश्मीर के पुराने राजनीतिज्ञों की गन्दी करतूतों की याद दिलाई जिन्होंने कश्मीर को इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत से जुदा कर दिया था।उन्होंने भारत को याद दिलाया कि उसी वेदना में से कमल खिला है। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि कश्मीर को अब एक नई राजनीति आकार दे रही है जो कश्मीर के लोगों को देश की अन्य हिस्सों के लोगों से जोड़ रही है। उन्होंने भारत को याद दिलाया कि विकसित भारत' के उनके मिशन का कश्मीर एक आवश्यक हिस्सा है और वह उसमें एक आवश्यक भूमिका निभाएगा।इसके पहले कि मैं नरेन्द्र मोदी की नई राजनीति' के पीछे की राजनीति की बात करूं और उनके नैरेटिव पर आऊं, थोड़ी चर्चा नए जम्मू-कश्मीर की। हो सकता है कि आप हर चीज़ में कुछ न कुछ नुक्स ढूँढने में माहिर हों, हो सकता है कि आप मोदी और उनके सरकार के अंध विरोधी हों, मगर फिर भी आप कश्मीर में आये बदलावों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। निसंदेह कुछ कश्मीरी एक ही सोच से चिपके रहना चाहते हैं।वहां के कुछ बुद्धिजीवियों की लिए कश्मीर की पहचान' (जिसकी परिभाषा बहुत साफ़ नहीं है) सबसे अहम, सबसे ऊपर है। फिर चाहे इसका मतलब सतत लूट, पहचान का राजनीतिकरण, उसे अन्य पहचानों से जुदा करना, लोगों को कट्टर बनाना, उनका दमन करना और कश्मीर की भूमि और उसकी पहचान को अतीत में धकेलना ही क्यों न हो।इसलिए यह ज़रूरी है कि हम द्वेष के लेंस लगे चश्मे उतार कर जम्मू-कश्मीर और विशेषकर घाटी में हुई प्रगति को देखें। कश्मीर को बहुत समय बाद विकास का स्वाद चखने को मिल रहा है, वह प्रगति और शांति, ग्लैमर और चमक-दमक का मज़ा ले रहा है। कश्मीर का मतलब अब हिंसा नहीं है। वहां शांति है। अल्पसंख्यकों की हत्याएं और सेना पर हमले कब-जब इस शांति को भंग करते हैं मगर तुलनात्मक रूप से शांति तो है ही।लोगों का मूड बदल रहा है। वे अब खुल कर बात करते हैं। वे अपने नए भविष्य, जो सुनहरा है, को गले लगाने तैयार हैं। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाके गुलज़ार हैं। निराशा भी उतनी निराशाजनक नहीं लगती। राजनीति में एक नयापन है, एक नया परिप्रेक्ष्य है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पूरी निष्ठा और समर्पण से इस कोशिश में लगे हैं कि प्रगति और उन्नति के साथ-साथ, राजनीति को भी जगह मिले, मगर एक नए कैनवास पर।नए कश्मीर में एक नई तरह की राजनीति अंगड़ाई ले रही है। अब्दुल्लाओं और मुफ्तियों की राजनीति उतनी ही दयनीय अवस्था को प्राप्त हो चुकी है जितनी कि राहुल गाँधी और तेजस्वी यादव की। निवेश आ रहा है, प्रगति हो रही है। सरकार की योजनाओं का फायदा पुलवामा के कश्मीरी को ही उतना ही मिल रहा है जितना बिहार के मांझी को।जैसा कि हम सब जानते हैं, आप कुछ करके ही मैदान जीत सकते हैं। केवल जुबानी जमाखर्च से कुछ होना-जाना नहीं है। कश्मीरियों को इस बात का अहसास है कि मोदी का जादू इस समय देश में सिर चढ़कर बोल रहा है और शक्ति और सत्ता मोदी के हाथों में केन्द्रित है। मोदी चुनाव के रणभूमि के भी विजयी योद्धा हैं। वे ही सब कुछ हैं।इसे कश्मीर की नियति कहें या और कुछ और मगर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पांच साल बाद भी वह चुनाव और सत्ता की खेल में महत्वपूर्ण मोहरा बना हुआ है। हालाँकि एक फर्क है। अब चर्चा हिंसा की नहीं होती। और यही मोदी की 7 मार्च की कश्मीर यात्रा को महत्वपूर्ण बनाता है।

-श्रुति व्यास-

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

महिला को देवी का रूप ऐसे ही नहीं कहा गया

महिला को देवी का रूप ऐसे ही नहीं कहा गया शीर्षक के माध्यम से लेखिका मुस्कान केशरी जी अपने एक और अनुभव को अपने पाठकों के साथ साझा कर रही है। जी यह 3 मार्च का अनुभव है। जैसे कि आप सभी को पता है मुस्कान केशरी जी को पटना में गार्गी अवार्ड सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। यह बहुत ही खास पल था। भारत के अलग- अलग जगहो से सभी सम्मानित सदस्य इस कार्यक्रम में आए थे। सम्मान समारोह का सत्र शुरू हुआ। सभी को आमंत्रित करके सभी को सम्मानित किया जा रहा है। एक ऐसी महिला को सम्मानित किया जा रहा था जो राष्ट्र स्तर पर लड़कियो के साथ जो रेप, बलात्कार जैसे दुर्व्यवहार होता है। उन लड़कियों को न्याय दिलवाने के लिए वो लड़ती है। उस महिला ने अपने साथ दो लड़कियों को लेकर आई। इस कार्यक्रम में जिनके साथ गैगरेप हुआ था जी हाँ! गैगरेप। बहुत ही छोटी लड़कियाँ और एक लड़की अपने माता - पिता के साथ आई, एक लड़की अपनी माँ के साथ। एक 17-18 लड़की के साथ तीन पुरुषों ने गैगरेप किया। उस महिला की मदद से गैगरेप करने वाले पुरुषों को 25 साल की जेल हुई और शायद 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। दूसरी लड़की उसके बारे में क्या बताए, जब लेखिका मुस्कान केशरी जी को पता चला। वो खुद इस सम्मान समारोह में रोने लगी। एक लगभग 18-20 साल की लड़की, जिसके साथ चार लोगो ने मिलकर गैंगरेप किया जिसके कारण आज वो दिमागी रूप में परेशान हो चूकी। हँसती खेलती लड़की को वो सबने बर्बाद करके छोड़ दिया उसकी हरकत देखकर आप भी एक पल में उदास जरूर होता उससे भी बुरा तब लगा जब पता चला कि पीड़िता की माता के जल जाने पर उसके पति ने उस महिला और अपनी बेटी को छोड़ दिया है। सोचिए एक ऐसी महिला जो खुद जली हुई हो, उसका पति छोड़ दिया हो, उसकी बेटी के साथ गैगरेप हुआ। यह समाज भी नहीं ही छोड़ा होगा जरूर दस बात सुनाया होगा। सब कुछ झेलते हुए आज वो महिला काम कर रही है और अपनी बेटी को साथ मे रखकर उसकी देख-भाल कर रही है। यह आसान बात नही है यह बहुत ही हिम्मत की बात है।

इसलिए कहा भी जाता है- इस दुनिया में माँ जैसा कोई रिश्ता नही,और सही में कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता है। हर कोई एक-दूसरे को छोड़ सकता है। लेकिन माँ का दिल तो दिल होता है। आज की अनुभव से यह सीख मिलता है-हालातों का क्या कहना, ये आते जाते रहते है। मुश्किलों से कहाँ भागना उसे सुलझाना होता है। बिल्कुल सुलझाए और हर रूप में मातृशक्ति को नमन करें...।

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर
बिहार

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

भाजपा के इस दांव में खतरे भी

लेकिन क्या भाजपा इस दांव में कामयाब हो पाएगी? कई बार इस तरह के दांव उलटे पड़ते हैं। कई बार कमजोर के प्रति सहानुभूति होती है। बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की डबल एंटी इन्कम्बैंसी हो सकती है। बिहार में जनता दल यू को साथ लेने के बाद भाजपा का पुरानी और छोटी सहयोगी पार्टियों से तालमेल बिगड़ा है क्योंकि उनको देने के लिए भाजपा के पास सीटें कम हैं।दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की पार्टियों में बेहतर तालमेल बना है। ध्यान रहे पिछली बार किशनगंज सीट पर मुकाबला इस वजह से था कि ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को करीब तीन लाख वोट मिल गए थे। इस बार ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए किशनगंज सीट पर कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के जीतने के चांस ज्यादा हैं। इसी तरह सीमांचल की अनेक सीटों पर और पिछली बार कांटे की टक्कर वाली यादव बहुल सीटों पर भी मुकाबला आसान नहीं है।पप्पू यादव के साथ आने से सीमांचल का गणित अलग ढंग से बन रहा है। सीमांचल में पूर्णिया से लेकर अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, खगडिय़ा, कटिहार तक पटना में पाटलिपुत्र और मगध में जहानाबाद जैसी सीटों पर कांटे का मुकाबला है।झारखंड में सिंहभूम सीट पर कोड़ा परिवार की मदद से भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत की है लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि वह पिछली बार की तरह 14 में से 12 सीट जीत जाए। पिछली बार तीन सीटों पर कांटे की टक्कर हुई थी। लोहरदगा में कांग्रेस नौ हजार और खूंटी में डेढ़ हजार वोट से हारी थी।दुमका में शिबू सोरेन भी 30 हजार के करीब वोट से हारे थे। इन सीटों पर इस बार भाजपा के लिए लड़ाई आसान नहीं है। इसके अलावा लहर के बावजूद पिछले दोनों चुनावों में भाजपा राजमहल सीट नहीं जीत पाई। ऐसा लग रहा है कि चार से छह सीटों पर विपक्षी गठबंधन बहुत मजबूत है। शास्त्रीय राजनीति के नजरिए से देखें तो ओडिशा में भाजपा ने वह गलती की है, जो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने और केरल में कांग्रेस व लेफ्ट मोर्चा ने नहीं की। ओडिशा में बीजू जनता दल और भाजपा सत्तारूढ़ व मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। उनके साथ आ जाने से विपक्ष का पूरा स्पेस कांग्रेस के लिए खाली हो गया। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 13 फीसदी वोट वाली पार्टी थी, लेकिन इस बार वह बीजू जनता दल और भाजपा दोनों के खिलाफ लड़ेगी तो दोनों का विरोधी वोट उसी की ओर जाएगा। बीजद और भाजपा का वोट पिछली बार 81 फीसदी से ऊपर था, जिसमें इस बार बड़ी कमी आएगी। अपनी लोकसभा की आठ सीटों में कुछ बढ़ोतरी के लिए भाजपा ने सत्तारूढ़ बीजद से तालमेल का फैसला किया है, जिससे विपक्ष का स्पेस एक बार कांग्रेस को मिलेगा, जो भाजपा के मुख्य विपक्षी बनने से तीसरे स्थान पर चली गई थी।इस बीच ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता गिरधर गमांग की पार्टी में वापसी हुई है तो तटीय ओडिशा के कद्दावर नेता श्रीकांत जेना भी लौटे हैं। वे तटीय ओडिशा की तीन अलग अलग सीटों से सांसद रह चुके हैं। सो, ऐसा न हो कि कांग्रेस को निपटाने का यह दांव भाजपा को भारी पड़ जाए?उत्तर प्रदेश में भाजपा का दांव अभी चल रहा है क्योंकि वहां राममंदिर का उद्घाटन हुआ है और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन वहां भी ज्यादा सीटें लडऩे की भाजपा की जिद के चलते सहयोगी पार्टियों को गिनी चुनी सीटें मिली हैं। हां, यह जरूर है कि भाजपा ने नए सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के एक नेता को मंत्री बना दिया है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओमप्रकाश राजभर को भी मंत्री बना दिया है।भाजपा ने अपनी चार सहयोगी पार्टियों को छह सीटों में निपटाया है। रालोद और अपना दल को दो-दो तो ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी को एक-एक सीट दी गई है। इनके साथ साथ भाजपा अपना पिछड़ा नेतृतव आगे कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी यादव मोह छोड़ कर अन्य पिछड़ी जातियों को ज्यादा सीटें दे रहे हैं।पिछली बार की तरह इस बार शिवपाल यादव की पार्टी उनको डैमेज नहीं कर रही है, बल्कि शिवपाल यादव अब साथ में हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती के निष्क्रिय होने से उनका वोट बिखर रहा है, जिसका एक हिस्सा सपा और कांग्रेस के साथ जा सकता है। इस बार 20 फीसदी के करीब मुस्लिम आबादी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि कांग्रेस और सपा साथ लड़ रहे हैं। ऊपर से पार्टी का आंतरिक कलह कई मामलों में देखने को मिला है।

-हरिशंकर व्यास-

फाग गीत

रंग लगाले घुम घुम के हो-2
आगे फागुन तिहार....
नाचत हे सब झुम झुम के..।।
गली गली मा बजे नंगारा हो,
बजे नंगारा।
किंजर किंजर के आरा-पारा हो,
आरा पारो ।
गावत हे गीत बिधुन होके हो...2
आगे फागुन तिहार...।।।
हरियर पिवंरी लाली गुलाली हो,
लाली गुलाली।
मोरो मन हर होगे मतवाली हो,
होगे मतवाली।
मन ला मिलाले रुमझुम के हो...2
आगे फागुन तिहार...।।।
मया पिरीत के नाता हावय जी,
नाता हावय।
जुरमिल के सब होली मनावै जी,
होली मनावै।।
मजा उड़ाले फागुन के हो...2
आगे फागुन तिहार...।।।

राजकुमार निषाद राज
गरियाबंद
छत्तीसगढ़

क्या-क्या फर्क पड़ेगा सीएए के लागू होने से ?

सीएए मतलब नागरिक संशोधन अधिनियम,इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बावजूद भी अभी तक भारतवर्ष में लागू नहीं किया जा सका था, इस कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कानून शुरुआत से ही विवादों के घेरे में रहा है। आईए जानते हैं इसके विवादों में रहने की वजह आखिरकार क्या है जिसके कारण आज तक यह हमारे देश में लागू नहीं हो पाया थाऔर अब जब इसके लागू हो जाने की अधिसूचना जारी हो ही गई आखिरकार तो आखिर किन-किन बातों का डर है जो कि आम जनमानस के दिमाग में घर कर रहा है। पहले भारतवर्ष की नागरिकता हासिल करना बहुत मुश्किल काम था लेकिन इस अधिनियम के लागू हो जाने से भारत के तीन पड़ोसी देश को भारत की नागरिकता प्राप्त करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार का कहना है कि हमारे तीन पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई,पारसी और हिंदू लोग जो कि वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए हम शरण देने के लिए वचनबद्ध हैं। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम लोगों को इसलिए भी नहीं लिया गया है क्योंकि यह तीनों देश बहुमुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। भारत देश में इस कानून को लेकर काफी प्रदर्शन और बवाल हो चुके हैं लेकिन एक बात इस कानून के लागू होने से तय है कि भारत में रह रहे लोगों के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है क्योंकि यह कानून भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए भारत के नागरिकता से संबंधित कानून है। एक तरफ अगर बात वैश्विक स्तर की की जाए तो पूरे विश्व में इस कानून को लेकर विभिन्न मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भारत की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा और मानव अधिकार उल्लंघन होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ लोगों को इस बात की भी चिंता स्ताई जा रही है कि देश में सत्तारूढ़ पार्टी बहुसंख्यक समुदाय के लोगों के वोट को अपने पक्ष में कर सकती है अर्थात इसको वोटो के ध्रुवीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारे देश में रह रहे किसी भी धर्म के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है और चूंकि इस कानून में मुस्लिम नागरिकता का प्रावधान नहीं है इसलिए इसको धार्मिक भेदभाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन माना जा रहा है। कुछ का कहना है कि इस कानून के लागू होने से अफगानिस्तान , पाकिस्तान तथा बांग्लादेश मैं रह रहे प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वहां की सरकार है उनको परेशान कर रहीं हैं। भारत देश एक बहुत विशाल देश है और यह दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। इस कानून के लागू होने से दूसरे देश के लोग जहां एक और भारत की नागरिकता लेकर इधर पलायन करेंगे तो वही इस देश के संसाधनों पर भी फर्क पड़ेगा, जिसका सीधा सीधा असर भारतीय नागरिकों पर पड़ेगा। अब चूंकि सीएए की अधिसूचना जारी हो गई है तो यहां एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हर कोई इस कानून का फायदा नहीं उठा सकता है। यह कानून किसी भी नागरिक को खुद नागरिकता प्रदान नहीं करता है बल्कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक या इससे पहले से भारत वर्ष में रह रहे हैं और उनप्रताड़ित लोगों की श्रेणी में आ रहे थे जिसका कि इस कानून के तहत जिक्र किया गया है, सिर्फ वही नागरिकता के पात्र होंगे। तीन-चार बातें जो ध्यान देने योग्य हैं वह यह है कि उन प्रताड़ित लोगों को यहां नागरिकता लेने से पहले यह साबित करना पड़ेगा कि वह सच ही में ही वहां पर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, उनको इस देश में रहते हुए जो समय अवधि हुई है वह भी साबित करनी होगी तथा उनका साथ में यह भी साबित करना पड़ेगा कि जो भारत की आठवीं अनुसूची में भाषण अनुसूचित हैं वह उन भाषाओं को बोलते हैं। इसके साथ-साथ उनका यह भी साबित करना पड़ेगा कि वह भारतीय नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को पूरा करते हैं, इसके बाद ही इस श्रेणी में आने वाले प्रताड़ित प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है।

डॉक्टर जय
महलवाल(अनजान)
बिलासपुर हिमाचल प्रदेश

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

भाव

कर्म पथ पर चलते जा
जीवन मे आगे बढ़ते जा।।
मुश्किलें तो कई आएगी
बेरियर जरूर बनाएंगी।।
इसे लक्ष्य अस्त्र से काटते जा
हौसला की पुड़िया बाटते जा।।
नव इतिहास अब तू गढ़ते जा
विजय गाथा की गीत गाते जा।।
रजा रजा मे जय हिंद गुंजाते जा
शत्रु को तुम यह बात बताते जा।।
भटके को राह मे लाते जा
सबको अपने मे मिलाते जा।।
समय की मांग को बताते जा
अपने दायित्व को निभाते जा।।
जग को हौसला दिखाते जा
खोई सब गौरव को तू पाते जा।।
आसमां पर तिरंगा लहराते जा
पूर्वजों की ख्वाब पूरा करते जा।।
कदम कदम बढ़ाये जा
वंदेमातरम् तू गाये जा।।
हर क्षेत्र मे देश को बढ़ाये जा
भारत माँ की जय घोष लगाये जा।।
अनेकता मे एकता बनाए रख
यह भाव तू मन मे जगाए रख।।
जात धर्म को एक हार मे पिरोए रख
भारतीय संविधान को तू सजोए रख।।

लक्ष्मी नारायण सेन
खुटेरी फिंगेश्वर
गरियाबंद छत्तीसगढ़

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

तू निरंतर आगे बढ़ते जा

दुनिया तुझ पर नाज करेगी,
सफलता की सीढ़ी चढ़ते जा।
मंजिल तुझे जरूर मिलेगी,
तू निरंतर आगे बढ़ते जा।।
कड़ी मेहनत से जी मत चुरा,
अपना भविष्य गढ़ते जा।
तेरा सपना न रह जाये अधूरा,
तू निरंतर आगे बढ़ते जा।।
राहों में चुनौतियां आएगी,
उन चुनौतियों से लड़ते जा।
सफलता तुझे जरूर मिलेगी,
तू निरंतर आगे बढ़ते जा।।
बाधाएं तुझे रोक नहीं पाएगी,
इन बाधाओं को पार करते जा।
लक्ष्य तुझे जरूर मिलेगी,
तू निरंतर आगे बढ़ते जा।।
बुलंदियों के पंख लगाकर,
खुले आसमान मे उड़ते जा।
पीछे मत देख कभी मुड़कर,
तू निरंतर आगे बढ़ते जा।।

श्याम सुंदर साहू
प्राचार्य राजिम
जिला गरियाबंद
छत्तीसगढ़

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

हर दृष्टि से सेहत के लिए हानिकारक है धूम्रपान

धूम्रपान के आदी मित्रों और परिजनों को धूम्रपान छोड़ने के लिए मदद पाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को 'नो स्मोकिंग डे' मनाया जाता है, जो इस वर्ष 13 मार्च को मनाया जा रहा है। यह दिवस पहली बार 1984 में आयरलैंड गणराज्य में मनाया गया था। प्रतिवर्ष यह दिवस एक खास विषय के साथ मनाया जाता है, जो इस साल 'तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा' विषय के साथ मनाया जा रहा है। दरअसल यह गहन चिंतन का विषय है कि पिछले कई दशकों में दुनियाभर में हुए अनेक अध्ययनों में यह प्रमाणित हो चुका है कि धूम्रपान हर दृष्टि से सेहत के लिए हानिकारक है लेकिन जब तमाम जानकारियों और तथ्यों के बावजूद हम अपने आसपास बच्चों को भी धूम्रपान करते देखते हैं तो स्थिति बेहद चिंताजनक प्रतीत होती है। ऐसे बच्चों के मनोमस्तिष्क में धूम्रपान को लेकर कुछ गलत धारणाएं विद्यमान होती हैं, जैसे धूम्रपान से उनके शरीर में चुस्ती-फुर्ती आती है, उनका मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है आदि-आदि। चूंकि बच्चों का मन कोमल होता है, इसीलिए तमाम वैज्ञानिक शोधों के बावजूद वे यह समझने की स्थिति में नहीं होते कि धूम्रपान करने से उनके अंदर ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं होने वाली कि देखते ही देखते वो किसी ऊंचे पर्वत पर छलांग लगा सकें या महाबली पवनपुत्र हनुमान की भांति विशाल समुद्र लांघ जाएं। वास्तविकता यही है कि धूम्रपान एक ऐसा धीमा जहर है, जो धीमे-धीमे इसका सेवन करने वाले व्यक्ति का दम घोंटता है और बच्चों पर तो इसका प्रभाव बहुत घातक होता है। धूम्रपान शरीर में कई प्रकार की प्राणघातक बीमारियों को जन्म देता है और ऐसे व्यक्ति को धीमी गति से मृत्यु शैया तक पहुंचा देने का माध्यम बनता है।

दुनियाभर में धूम्रपान के कारण हर साल 70 लाख से भी ज्यादा मौतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में होने वाली मौतों में से हर 5 में से 1 पुरूष की मौत धूम्रपान के कारण हो रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार माना गया है कि विकसित देशों में चालीस फीसदी से ज्यादा पुरूष और इक्कीस फीसदी से ज्यादा स्त्रियां धूम्रपान करती हैं जबकि विकासशील देशों में सिर्फ आठ फीसदी स्त्रियों को इसकी लत लगी है तथा पुरूषों की संख्या पचास फीसदी से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तम्बाकू के सेवन के कारण प्रतिदिन करीब आठ हजार व्यक्ति फेफड़ों के कैंसर के शिकार होकर मर जाते हैं। संगठन का अनुमान है कि यदि दुनियाभर में धूम्रपान की लत ऐसे ही बढ़ती रही तो बहुत जल्द धूम्रपान के कारण पचास करोड़ लोग मारे जा चुके होंगे और अगले तीस वर्षों में केवल गरीब देशों में ही धूम्रपान से मरने वालों की संख्या दस लाख से बढ़कर सत्तर लाख तक पहुंच जाएगी। संगठन का अनुमान है कि प्रतिवर्ष विश्वभर में आठ हजार से ज्यादा नवजात शिशु धूम्रपान की वजह से असमय काल के ग्रास बन जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी प्रकार के कैंसर में से करीब 40 फीसदी का कारण धूम्रपान ही होता है। तीन दशक पूर्व प्रकाशित अपनी पुरस्कृत पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' में मैंने विस्तार से यह बताया है कि धूम्रपान वास्तव में एक ऐसा धीमा जहर है, जो हमारे शरीर में धीरे-धीरे प्राणघातक रोगों को जन्म देता है और व्यक्ति को धीमी गति से मृत्यु शैया पर पहुंचा देता है। धूम्रपान कितना खतरनाक है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सिगरेटों के खतरनाक धुएं से करीब 50 टन तांबा, 15 टन शीशा, 11 टन कैडमियम तथा कई अन्य खतरनाक रसायन वातावरण में घुलते हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कैंसर, हृदय रोग, सांस की बीमारी, डायबिटीज इत्यादि बीमारियों में भी धूम्रपान काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धूम्रपान से बचना चाहिए।

अपनी पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' में मैंने विस्तार से यह बताया है कि सिगरेट के धुएं में पोलिनियम 210, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइआक्साइड, निकल, पाईरीडिन, बेंजीपाइरीन, नाइट्रोजन आइसोप्रेनावाइड, अम्ल, क्षार, निकोटीन, टार, जिंक, हाइड्रोजन साइनाइड, कैडमियम, ग्लायकोलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, एसीटिक एसिड, फार्मिक एसिड, मिथाइल क्लोराइड इत्यादि चार हजार से भी ज्यादा घातक रासायनिक तत्व विद्यमान होते हैं, जो मानव शरीर को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। गर्भवती महिलाओं द्वारा धूम्रपान किए जाने से कम लम्बाई और कम वजन के बच्चों का जन्म, बच्चों में अपंगता तथा बाल्यावस्था में ही घातक हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। प्रतिदिन बीस सिगरेट तक पीने वाली गर्भवती महिला के बच्चे की मृत्यु होने की संभावना सामान्य के मुकाबले बीस फीसदी बढ़ जाती है जबकि बीस से अधिक सिगरेट पीने पर यह खतरा पैंतीस फीसदी तक हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक किसी दूसरे के धूम्रपान के धुएं के प्रभाव से दिल के दौरे से होने वाली मौतों की आशंका तीस फीसदी बढ़ जाती है।

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,
नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

घटती-घटना खबर का बड़ा असर...

भूमि गबन मामले में नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो, आरआई राहुल सिंह,नारायण सिंह सहित बाबू अजय तिवारी के विरुद्ध हुआ एफआईआर दर्ज

दैनिक घटती-घटना खबर पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान और मामला पहुंचा एफआईआर तक

- » कलेक्टर सरगुजा ने मामले में अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को किया तलब...
- » अंबिकापुर राजमोहिनी के पीछे की नजूल भूमि के गबन मामले कलेक्टर ने की थी एफआईआर की अनुशंसा
- » बेस कीमती राजमोहिनी के पीछे की नजूल भूमि गबन मामले की जांच हुई पूरी...
- » जमीन गबन मामले में एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी निभाई अपर कलेक्टर सुनील कुमार नायक ने...
- » जमीन गबन मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले दस्तावेज की कमियों को किया गया पूरा...
- » इस मामले की जांच कलेक्टर सरगुजा ने निष्पक्ष कर पेश की मिसाल... जिससे एफआईआर दर्ज हो गई... जो अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही...

-भूपेन्द्र सिंह -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

सत्ता परिवर्तन के बाद ही सही पर शहर के राजमोहनी भवन के पीछे स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि के क्षति मामले में आज तात्कालीन नजूल अधिकारी,दो आरआई और जिला नजूल कार्यालय में पदस्थ बाबू पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार जांच में अभी और एक दर्जन से ज्यादा नाम जुड़ने की संभावना है। उक्त मामले में कलेक्टर सरगुजा ने अनावेदक बंसू सहित 8 अनावेदकों को कलेक्टर न्यायालय में 14 मार्च को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। इतनी बड़ी कार्यवाही दैनिक घटती घटना खबर का असर है लगातार खबर प्रकाशन के बाद अंततः मामला कार्यवाही तक पहुंचा अब तक की यह सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार राजमोहनी देवी भवन के पीछे स्थित लगभग सवा 4 एकड़ गोचर मद की भूमि को राजस्व के अधिकारियों-कर्मचारियों ने भूमाफियों से सांठगांठ कर बंसू आ.भटकुल के नाम दर्ज करा कौड़ियों के दाम पर बेचे जाने के मामले में प्रशासन के बाद अब पुलिस ने भी कार्यवाही शुरू कर कर दी है। कल देर रात प्रशासन ने तात्कालिन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो (वर्तमान में कोंडागांव जिले में संयुक्त कलेक्टर), राहुल सिंह आरआई, नारायण सिंह आरआई एवं नजूल कार्यालय का बाबू अजय तिवारी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 467, 468, 420, 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मामले में जांच के दौरान फर्जीवाड़े में अभी और आरोपियों के नाम शामिल होने की संभावना है।

विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू के नाम हुई भूमि

उल्लेखनीय है कि तहसीलदार (नजूल) अंबिकापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नमनाकला, अंबिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि सरगुजा सेटलमेंट मे गोचर मद की भूमि है, जिसे अनियमित पट्टा और विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू द्वारा अपने नाम पर कराते हुये उक्त शासकीय नजूल भूमि में से कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। जिसमें अनावेदक सतीश शर्मा,सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव,शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल,अनुषा नागदेव,महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार शामिल हैं। इससे शासन को शासकीय भूमि की क्षति हुई है।

क्या है बंशु लोहार आत्मज भुटकुल का पूरा मामला...

आवेदक कमल सिंह की मानें तो नगर अम्बिकापुर में राज मोहनी भवन के पास मोहल्ला नमना कला अंबिकापुर में खसरा नंबर 243 स्थित है,उक्त भूमि पूर्व में 111.40 एकड़ भूमि थी। जो कालांतर में शासकीय प्रयोगों के लिए उपयोग में लाई गई और कुछ भूमि पर शासन के द्वारा पट्टा प्रदान किया गया तथा इसी से संबंधित भूमि पर व्यवहारवाद क्रमांक 41-ए-90 निर्णय दिनांक 23.09.1991 विचाराधीन था जिस पर निर्णय पारित किया गया है और वर्तमान में

उक्त भूमि का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय,बिलासपुर में विचाराधीन है। उक्त भूमि वर्तमान नक्शे में दत्ता कॉलोनी की भूमि खसरा नंबर 243 को भूमि डिग्री भूमि 233 के भाग में फर्जी तौर से समाहित कर नक्शा तैयार किया गया है। जबकि 233 खसरा नंबर भूमि का प्रकरण व्यवहारवाद में विचाराधीन था। जिसका अभी निराकरण नहीं होना बताया गया है। इसी दौरान तात्कालीन नजूल अधिकारी,अंबिकापुर के न्यायालय में भू-माफिया द्वारा बन्सु आ0 भुटकुल लोहार निवासी-फुन्दुरडिहारी,अंबिकापुर जिला सरगुजा के माध्यम से एक राजस्व प्रकरण./अ-6/2021-22 में दिनांक 06.10.2022 को आदेश पारित किया गया है कि बंशु आ0 भुटकुल के द्वारा नजूल भूमि खसरा नंबर 154,243/10 रकबा क्रमशः 0.934,1.710 भूमि का पट्टा तहसीलदार अंबिकापुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 1967-68 आदेश दिनांक 15.04.1968 के माध्यम से मोहल्ला नमना कला नगर अंबिकापुर में स्थित नजूल भूमि भू खण्ड क्रमांक खसरा नंबर 154, 243/10 रकबा क्रमशः 934, 1.710 का पट्टा प्रदान किया गया है। किन्तु राजस्व अभिलेखों में नाम विलोपित हो गया है। जिसके आधार पर तात्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो तथा नजूल अधिकारी के लिपिक अजय तिवारी एवं हल्का पटवारी गणेश मिश्रा व राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह द्वारा मिलकर शासन की 60 करोड़ रूपये की भूमि का 04 करोड़ रूपये में मिलकर भू-माफियाओं से अवैध धन की उगाही कर भ्रष्टाचार कर नियम विरूद्ध शासकीय भूमि को बंशु आ0 भुटकुल के नाम दर्ज करने का आदेश दिनांक 06.10.2022 को पारित करवा कर उक्त भूमि को अवैध प्लाटिंग कर 15-15 लाख रूपये प्रति डिसमिल से विक्रय किया जा रहा था। यह बहुत बडे भू-माफियाओं से मिलकर किया गया भूमि घोटाला माना जा रहा है। जिसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायहित में जनहित के लिए आवश्यक बताया गया है।

कई और नाम शामिल होंगे एफआईआर में

राजमोहिनी भवन शासकीय भूमि के फर्जीवाडें मामले में अभी तक चार नाम के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध हुआ बाकी अभी अन्य में है सूत्रों का कहना है कि अभी कई ऐसे नाम आएंगे जिनका नाम भी इस अपराध में जुड़ेगा और उन पर भी इन धाराओं के तहत बड़ी कार्यवाही होगी, बहुत जल्द वह नाम भी इसमें शामिल होंगे जिसका खुलासा किया जाएगा।

क्या एफआईआर के बाद अधिकारी व कर्मचारी होंगे बर्खास्त?

जिस नजूल अधिकारी आरआई सहित बाबु पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है क्या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी, ऐसा करने से बाकी अधिकारी कर्मचारी भी घबराएंगे,यह कार्यवाही कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

अपराध दर्ज करने के बाद पूरे दिन कलेक्टर कार्यालय में दस्तावेज खंगालते रही पुलिस

अपराध दर्ज होने के बाद कलेक्टर कार्यालय में कोतवाली पुलिस मामले के दस्तावेज को खंगालती रही और जांच में जुटी रही ताकि जमीन फर्जीवाड़े वाले मामले में जिन-जिन लोगों की संलिप्ता है सभी पर अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा सके।

शासकीय जमीन निजी हाथों में देने के मामले में राजस्व कर्मचारी व अधिकारी पर अपराध दर्ज

अंबिकापुर शहर की बेश कीमती राज मोहिनी भवन के पीछे की शासकीय जमीन को अधिकारी कर्मचारियों के मिलीभगत से निजी हाथों में दे दिया गया था, इतने बड़े फर्जी वाले मामले में दैनिक घटती-घटना के खबर प्रकाशन के बाद मामला उजागर हुआ और अधिकारी सहित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, अभी तक कई जमीन फर्जीवडा मामला आया होगा पर अभी तक कर्मचारी व अधिकारी बच निकलते थे, पहली बार निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही की गई जिसमें अधिकारी व कर्मचारियों पर भी अपराध दर्ज किया गया,ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि स्वच्छ छभी वाले सरगुजा कलेक्टर भोस्कर बिलास संदीपन ने इतनी बड़ी कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाई और अपना स्वच्छ छवि लोगों के सामने रखा... सरगुजा कलेक्टर की यह कार्रवाई ने आने वाले समय के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को बहुत बड़ी सीख दे दी है।

घटती घटना ने प्रमुखता से उठाया मुद्दा

कलेक्टर न्यायालय में बंसु सहित 8 अनावेदक का बुलावा

इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण को छग भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण में ग्राहय कर सुनवाई किया जा रहा है। इस प्रकरण में अनावेदक बंसु आत्मज भटकुल निवासी फुन्दुरडिहारी, तहसील अंबिकापुर एवं उपरोक्त 08 अनावेदकगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु पेशी तिथि दिनांक 14 मार्च 2024 को 3.00 बजे दोपहर को नियत किया गया है। कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी अनावेदकगण उक्त पेशी तिथि में कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को अनावेदकगण यदि जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रकरण में एकपक्षीय रूप से अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण में गुण दोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जायेगा।

राष्ट्रपति जरदारी और गृहमंत्री नकवी ने किया वेतन छोड़ने का एलान,देश की आर्थिक तंगी का दिया हवाला

इस्लामाबाद,12 मार्च 2024। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान वेतन नहीं लेंगे। नव नियुक्त राष्ट्रपति ने अपने इस निर्णय के पीछे देश की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। जरदारी ने कहा कि उनका ये निर्णय नकदी संकट से जूझ रहे देश को आर्थिक कठिनाई का सामना करने में मदद करने की कोशिश है। उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। राष्ट्रपति सचिवालय ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बारे में जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खजाने पर बोझ नहीं डालने के लिए अपना वेतन छोड़ दिया है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को प्रति माह 8,46,550 रुपये मिलते थे, जो 2018 में संसद द्वारा तय किया गया था।

देश के अमीर राजनेताओं में शामिल हैं जरदारी

गौरतलब है कि जरदारी पाकिस्तान के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने रविवार को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने इस्लामाबाद में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जरदारी को पद की शपथ दिलाई। सैन्य शासकों को छोड़कर जरदारी दूसरी बार राष्ट्र प्रमुख का पदभार संभालने वाले पाकिस्तान के पहले नेता बन गए हैं। इससे पहले वह 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाल चुके हैं।

मोहसिन नकवी ने भी वेतन छोड़ने का किया एलान

उनके अलावा, पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने भी अपना वेतन छोड़ने का फैसला किया है। नकवी ने भी इसके पीछे देश के सामने चल रही आर्थिक चुनौतियों का हवाला दिया। एक्स पर एक पोस्ट में नकवी ने कहा कि संकट के इस समय में हर संभव तरीके से देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

छह साल बाद ब्रिटेन से पाकिस्तान लौटे नवाज के बेटे,पनामा पेपर मामले में जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट

इस्लामाबाद,12 मार्च 2024। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोनों बेटे छह साल के आत्म-निर्वासन के बाद मंगलवार को लंदन से अपने देश लौट आए। हसन नवाज और हुसैन नवाज का नाम 2016 में पनामा पेपर घाटाले में आया था। जिसके बाद दोनों ने 2018 में देश छोड़ दिया था। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसे एक जवाबदेही अदालत ने हाल ही में रद्द कर दिया।

जवाबदेही अदालत ने 2018 में एवेनफील्ड मामले में दोनों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। एवेनफील्ड मामल शरीफ परिवार के स्वामित्व और लंदन में लग्जरी अपार्टमेंट के अधिग्रहण से जुड़ा है।

सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी ने एक बयान में कहा, नवाज के बेटे मंगलवार को लंदन से यहां पहुंचे। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर के उनके जाती उमरा आवास पर ले जाया गया।

पायल व नगदी चोरी करने वाले आरोपी को थाना रामानुजनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

- संवाददाता -
सूरजपुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

ग्राम कैलाशपुर रामानुजनगर निवासी बेचूराम साहू ने थाना रामानुजनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 7 मार्च को गांव में शादी था जहां पूरे परिवार सहित गया था वापस घर आया तो देखा कि आलमारी खुला था जिसमें रखा पायल, बिझियां व नगदी रकम वहां नहीं था कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 457, 380 भादसं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

थाना रामानुजनगर पुलिस चोर की पतासाजी करने के दौरान मुखबीर की सूचना पर निलेश देवांगन उर्फ नान दाउ पिता धीरेन्द्र देवांगन उम्र 19 वर्ष ग्राम कैलाशपुर, थाना रामानुजनगर को पकड़ा। पूछताछ पर उसने बेचूराम के यहां चोरी करना स्वीकार कर बताया कि नगदी रकम को खाने-पीने में खर्च कर दिया है। आरोपी के निशानदेही पर एक जोड़ी बिछिया, 1 जोड़ी पायल कीमत 6300 रूपये का जप्त कर आरोपी निलेश देवांगन को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर प्रकाश राठौर, एएसआई मनोज पोर्ते, बिसुनदेव पैंकरा, प्रधान आरक्षक हंसराम कनेडिया, आरक्षक विनोद दास,कौशलेन्द्र सिंह व रूपदेव सिंह सक्रिय रहे।

सड़क हादसे में घायल युवक की मौत

- संवाददाता -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

बैकुंठपुर के डीहाईपारा में 11 मार्च की रात को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंग में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजू यादव पिता शिवकुमार यादव उम्र 34 वर्ष जनकपुर थाना बैकुंठपुर का रहने साला था। वह 11 मार्च की रात को बाइक से कहीं जा रहा था। तभी डीहाईपारा बचरापोड़ी के पास एक अन्य बाइक से भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में राजू गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। परिजन उसे इलाज के लिए बैकुंठपुर अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

संयुक्त संचालक शिक्षा हेमंत उपाध्याय का तबादला,संजय गुप्ता को मिली जिम्मेदारी

- संवाददाता -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

संयुक्त संचालक सरगुजा शिक्षा विभाग हेमंत उपाध्याय का तबादला

कर एससीईआरटी में पदस्थ किया है। वहीं संजय गुप्ता अब हेमंत उपाध्याय की जगह सरगुजा संयुक्त संचालक की जिम्मेदारी संभालेंगे। जारी आदेश में पदोन्नति संशोधन मामले में हेमंत उपाध्याय के निलंबन के बाद 14 जून 2023 को राज्य सरकार ने संजय गुप्ता को डीईओ जशपुर से सरगुजा संयुक्त संचालक नियुक्त किया था। संजय गुप्ता ने 21 अगस्त 2023 को कार्यभार ग्रहण कर काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसी दौरान दिसंबर 2023 में पदोन्नति संशोधन मामले में निलंबन को दी गयी चुनौती पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हेमंत उपाध्याय सहित सभी संयुक्त संचालकों को पूर्व की पदस्थापना स्थल पर काम करने का आदेश दे दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार 11 मार्च को आदेश निकालकर हेमंत उपाध्याय को हटाते हुए रायपुर पदस्थ किया है।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 81 वाहन चालकों से वसूले गए 53 हजार समन शुल्क

- संवाददाता -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)। सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगाकार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार की शाम को यातायात पुलिस द्वारा वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले 32 लोगों से 9 हजार 6 सौ रुपए व बाइक में तीन सवारी चलने वाले 15 लोगों से 7 हजार 5 सौ रुपए, मॉडिफाइड साइलेंसर के 1 मामले में 5 हजार रुपए व भारी वाहनों के अवैध पार्किंग के मामले में 6 लोगों से 4 हजार 350 रुपए समन शुल्क की वसूली की गई है। 81 वाहन चालकों से कुल 53 हजार 50 रुपए समन शुल्क वसूले गए हैं। सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रतिदिन कार्यवाही की जायगी,सरगुजा पुलिस आमनागरिकों से अपील करती है कि यातायात के नियमो का पालन करें स्वयं सुरक्षित रहे एवं अन्य राहगीरो कों भी सुरक्षित रखे।

425 समंस,205 जमानती वारंट,2 गिरफ्तारी वारंट, 4 स्थाई वारंट की की गई तमिली

- संवाददाता -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

सरगुजा पुलिस द्वारा जिला मुख्यालय समेत समस्त थाना, चौकी में लंबित समंस, जमानतीय वारंट, गिरफ्तारी वारंट एवं स्थाई वारंट की तमिली हेतु तीन दिवसीय अभियान चलाकर अधिक से अधिक समंस एवं वारंटो की तमिली करने हेतु निर्देशित किया गया था। अभियान के तहत दो दिनों के भीतर थाना कोतवाली द्वारा 4 स्थाई वारंट, 27 जमानतीय वारंट,109 समंस, तमिल किया गया, थाना गांधीनगर द्वारा 30 जमानतीय वारंट एवं 26 समंस तमिल किया गया, थाना मणीपुर द्वारा 12 जमानतीय वारंट, 44 समंस, थाना लखनपुर द्वारा 02 गिरफ्तारी वारंट 24 जमानतीय वारंट, 33 समंस, थाना लुन्ड्रा द्वारा 09 जमानतीय वारंट एवं 14 समंस,थाना दरिमा द्वारा 02 जमानतीय वारंट, 26 समंस, थाना उदयपुर द्वारा 13 जमानतीय वारंट एवं 33 समंस, थाना धौरपुर द्वारा 05 जमानतीय वारंट एवं 5 समंस, थाना बतौली 22 जमानतीय वारंट, 40 समंस, थाना सीतापुर द्वारा 36 जमानतीय वारंट एवं 50 समंस, थाना कमलेश्वरपुर द्वारा 10 जमानतीय वारंट एवं 14 समंस, महिला थाना द्वारा 2 जमानतीय वारंट एवं 2 समंस, थाना अजाक द्वारा 4 जमानतीय वारंट एवं 1 समंस, चौकी रघुनाथपुर द्वारा 6 जमानतीय वारंट एवं 17 समंस, चौकी कुन्री द्वारा 5 समंस, चौकी केदमा द्वारा 5 समंस, चौकी केरजू द्वारा 3 जमानतीय वारंट एवं 1 समंस तामिल किया गया हैं, अभियान के तहत कुल 425 समंस, 205 जमानतीय वारंट, 2 गिरफ्तारी वारंट एवं 4 स्थाई वारंट तमिल किया गया हैं,सरगुजा पुलिस द्वारा उक्त अभियात के तहत आज भी लंबित समंस वारंट की तमिली की जायगी।

शराब के नशे में धुत नाती ने दादी को डंडे से की पिटाई,सिर में चोट लगने से हुई मौत

- संवाददाता -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा में 10 मार्च की शाम को एक युवक ने शराब के नशे में परिवार के सदस्यों के साथ विवाद कर रहा था। इस दौरान दादी ने उसे विवाद करने से मना की तो नाराज होकर युवक ने दादी के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारने के लिए दौड़ाने लगा तो लोग घर से भाग गए। रिपोर्ट पर दरिमा पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।

पुलिस के अनुसार राजू नागेसिया उम्र 24 वर्ष ग्राम कर्रा थाना दरिमा का रहने वाला है। वह 10 मार्च की शाम को गांव से शराब पीकर घर आया और घर वालों के साथ विवाद करने लगा। इस दौरान इसकी दादी बिहानी बाई उसे विवाद करने से मना करने लगी। इस बात से नाराज होकर नशे में धुत नाती ने डंडे से दादी की बेदम पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे घर वालों को भी मारने के लिए दौड़ाने लगा। लोग डर से घर से भाग गए। वहीं सिर में गंभीर चोट लगने से दादी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका बिहानी बाई के दामाद संजय कुमार ने मामले की जानकारी दरिमा थाना को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। घटना के बाद आरोपी घर से भाग गया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी नाम राजू नगेसिया के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कार्रवाई में थाना दरिमा से सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ लकड़ा, आरक्षक अभय चौबे, दुर्गेश राजवाड़े शामिल रहे।

विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान मौत

- संवाददाता -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

हत्या के मामले में रामानुजगंज जेल में बंद विचाराधीन बंदी की मौत हो गई। तबियत विगडने पर उसे केन्द्रीय जेल अंबिकापुर से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहर साय पिता फिरनु राम उम्र 55 वर्ष बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम सिविलदाग का रहने वाला था। वह हत्या के मामले में रामानुजगंज जेल में विधाराधीन बंदी था। 11 मार्च को उसकी तबियत बिगडने पर उसे इलाज के लिए रामानुजगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था। रामानुजगंज जेल प्रशासन ने उसे पहले केन्द्रीय जेल अंबिकापुर भेजा। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई।

लखनपुर के 10927 किसानों को 56.02 करोड़ राशि का मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में किया अंतरण

- संवाददाता -
लखनपुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

12 मार्च दिन मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि उन्नति योजना खरीफ के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72000 से अधिक किसानों को 13320 करोड रुपए आदान सहायता राशि का किसानों के बैंक खातों में अंतरण किया। तो वहीं लखनपुर विकासखंड के 10927 किसानों के के खातों में 56.02 करोड़ आदान सहायता राशि का किसानों के बैंक खाते में अंतरण किया। मिली जानकारी के मुताबिक लखनपुर विकासखंड के 7 उपार्जन केंद्र 2 उपकेंद्र के पंजीकृत किसानों की संख्या 12090 में से 10927 किसानों ने 6 लाख 11199.20 क्विंटल धान 133.42 करोड रुपए का धान बिक्री किया है। जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कृषि उन्नति योजना अंतर्गत लखनपुर विकासखंड के 10927 किसानों के खातों में अंतर की राशि 56.020 करोड़ रुपए सीधे अंतरण किया। कृषि उन्नति योजना अंतर्गत लखनपुर जनपद पंचायत कार्यालय की सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जहां अतिथि के रूप में जनपद अध्यक्ष मोनिका सिंह पर जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंह देव भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू नगर पंचायत उपाध्यक्ष रामनारायण दुबे अपर कलेक्टर ध्रुव सहित भाजपा के पदाधिकारी गण मौजूद रहे।

मोदी संवाद सम्मेलन में रायपुर मे चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर योगदान कार्य करने वाले लखनपुर के डॉ.सलमान खान को सम्मानित किया गया

- संवाददाता -
लखनपुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

रायपुर किंग्सवे होटल रविवार10 मार्च भारतीय जनता पार्टी के मोदी के संवाद सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन सिंह ,भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव द्वारा रायपुर स्थित प्राइवेट हॉस्पिटलों में चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टर को सम्मानित किया गया लखनपुर वार्ड क्रमांक 6 के निवासी डॉक्टर सलमान खान पिता कलीम खान जो की रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। लगातार 5 वर्षों से अस्पताल में चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया इसके कार्यक्रम के दौरान रायपुर में स्थित संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर सुरभि चोपड़ा,डॉ उमेश चंद्रा,डॉ एजाज फारुकी को अस्पतालों में मरीजों के बेहतर तरीके से सेवा भाव के साथ योगदान देने पर कार्यक्रम में डॉक्टर को आमंत्रित करके बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मोदी संवाद सम्मेलन में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा जनप्रतिनिधि और रायपुर डॉक्टर मौजूद रहे।

डाइट में प्रशिक्षण लेने आई शिक्षिका की 4 वर्षीय बेटी पानी की टंकी में गिरी,डूबकर मौत

- संवाददाता -
अंबिकापुर,12 मार्च 2024 (घटती-घटना)।

शहर के बनारस मार्ग पर स्थित डाइट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) में संभाग के प्राइमरी स्कूल के प्रधानपाठकों व शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक (एफएलएन) पर आधारित 3 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। मंगलवार को प्रशिक्षण शामिल होने आई एक शिक्षिका अपनी 4 वर्षीय मासूम बेटी को भी लाई थी। महिला प्रशिक्षण में व्यस्त थी, जबकि बेटी इधर-उधर खेल रही थी। इसी बीच बेटी डाइट परिसर में ही स्थित पानी से भरी टंकी में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। शिक्षिका ने जब उसे खोजना शुरु किया तो वह टंकी में मिली। बेटी को इस हाल में देख वह बेसुध हो गई और उसके रोने का ठिकाना नहीं रहा। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की।

अंबिकापुर के डाइट में शिक्षकों का 3 दिवसीय एफएलएन का प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण 11 मार्च से 13 मार्च तक होना है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर ब्लॉक निवासी लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलदगी के भंडारपारा प्राइमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षिका कलावती सिंह भी प्रशिक्षण लेने मंगलवार को पहुंची थी। साथ में वह अपनी 4 वर्षीय बेटी ध्वनी को भी लेकर आई थी। दोपहर करीब 12.30 बजे वह कक्षा में बैठकर प्रशिक्षण ले रही थी, वहीं उसकी बेटी आस-पास ही खेल रही थी। करीब 10 मिनट बाद जब शिक्षिका ने देखा कि उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है तो उसने उसे खोजना शुरु कर दिया। अन्य शिक्षक भी उसकी खोजबीन में लग गए। इसी बीच अचानक उनकी नजर डाइट परिसर में स्थित पानी की टंकी के पास गई तो बालिका उसमें डूबी थी। ये नजारा देखते ही वहां कोहराम मच गया। घटना के बाद वहां मौजूद शिक्षकों द्वारा ही पानी की टंकी से बालिका को किसी तरह बाहर निकाला गया। फिर कार से उसे गांधीनगर स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

क्या 8 साल पूर्व कोतवाली बैकुण्ठपुर में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध बिना नाम दर्ज एफआईआर मामले में बिना पुलिसकर्मियों के नाम के ही चालान हुआ पेश ?

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और 8 साल बाद बिना पुलिसकर्मियों नाम के ही चालान पेश हो गयाःसूत्र

क्या उच्च अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए 8 साल का लंबा इंतजार किया और बिना कर्मचारियों के नाम के ही चालान पेश किया ?

पीड़ित को परेशान करने वाले भी पुलिसकर्मी और परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों की जांच का जिम्मा संभालने वाली भी पुलिस...क्या इसी वजह से पीड़ित को मिलने वाले न्याय के बीच जांच अधिकारी बने बाधा और पुलिसकर्मियों को बचाया ?

न्याय की लड़ाई लड़ने वाली भी दुनिया छोड़ गई न्याय की उम्मीद में लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद क्या न्याय उसको क्या मिलना नहीं था जायज ?

न्यायालय आदेश के बाद तकालीन थाना प्रभारी व प्रधान आरक्षक के विरुद्ध मामल हुआ था पंजीबद्ध पर नाम को छिपाकर हुआ था मामला दर्ज

मामला पंजीबद्ध होने के बाद बिना जमानत व विभागीय जांच के पुलिसकर्मी आज भी कैसे डटे है नौकरी में ?

जहां एफआईआर दर्ज होते ही नौकरी से पृथक होना था पर प्रभाव में आज भी काट रहे नौकरी का मजा

आमजनों पर मामला पंजीबद्ध करना पुलिस के लिए आसान पर पुलिस पर मामला पंजीबद्ध करें कौन ?

8 साल बाद भी आरोपी पुलिसकर्मियों का चालान पेश न होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है ?

-रविं सिंह-
बैकुण्ठपुर,12 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

8 साल पहले कोरिया जिले के कुछ पुलिसकर्मियों के ऊपर जबरन बिना किसी आदेश के अतिक्रमण हटाने को लेकर शिकायत हुई थी पर शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई थी, जिसके बाद प्रार्थी ने उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी जिसके बाद उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश के दबाव में एफआईआर तो दर्ज किया पर पुलिसकर्मियों का नाम नहीं लिखा,जबकि आदेश में नामजद एफआईआर दर्ज करना था पर ऐसा हुआ नही। अब जब सरकार बदल गई है तब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही होगी और उनके ऊपर विभागीय जांच सहित इन्हें पद से पृथक किया जाएगा? यह सवाल बना हुआ था पर जैसे ही सत्ता बदली इस

मामले की जांच अधिकारी ने अपने विभाग के पुलिसकर्मियों के बचाव करते हुए बिना पुलिसकर्मियों के बिना नाम के ही चालान को अन्य आरोपियों के नाम से दिसंबर माह में न्यायालय में पेश कर दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया,तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने भी इस मामले में पुलिसकर्मियों को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और

जाते-जाते इन पुलिसकर्मियों को राहत की सांस लेने का मौका दे दिया पर वही पीड़ित के न्याय लिए किसी ने नहीं सोचा जिसकी झोपड़ी तोड़ने यह पुलिसकर्मी किसी के कहने पर बिना आदेश के पहुंच गए थे और उस गरीब को खूब सताया था वह वृद्ध गरीब महिला न्याय की लड़ई लड़ रही थी और इस बीच उसका निधन भी हो गया पर ऐसा लगा कि उसके निधन के बाद ही शायद उसको न्याय मिल जाए पर ऐसा होता नहीं दिखा, पुलिस वालों ने अपने पुलिसकर्मियों की गलतियों पर पर्दा डालते हुए उनके नाम को एफआईआर से लेकर चालान पेश करने तक दूर रखा और 8 साल के इंतजार के बाद चालान पेश कर अपना एक झमेला दूर कर लिया पर वही पीड़ित की न्याय की लड़ाई में रसूखदार पुलिसकर्मियों को उनके जांच अधिकारी ने बचा लिया। जांच अधिकारी ने भी कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया।

अब चालान पेश हो गया है और बताया जाता है की चालान को देखकर समझा जा सकता है की कैसे पुलिस ने पुलिस को बचाया क्योंकि जांच उनके ही पास थी अन्य कोई होता वह जेल जाता यह भी तय था बस पुलिस ने पुलिस को बचाया यह कहा जा सकता है और न्याय को केवल इसलिए हाशिए पर डाल दिया क्योंकि मामले में पुलिसकर्मी फंसते नजर आ रहे थे।

ज्ञात हो कि किसी भी अधिकारी के लिए उनके सारे कर्मचारी एक समान होते हैं पर किसी एक कर्मचारी को विशेष महत्व देना कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है कुछ ऐसा ही मामला कोरिया जिले के पुलिस विभाग का है जहां पर एक प्रधान आरक्षक पर अधिकारियों का आशीर्वाद बरसता रहता है अब इसकी वजह चाहे जो भी हो, कोरिया के एक प्रधान आरक्षक हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं इनके खिलाफ शिकायतों का अंबार है पर जो भी अधिकारी आता है वह इस प्रधान आरक्षक का मुरीद हो जाता है ना जाने ऐसा कौन सा गुण है इनमें की जो यह बोल दे वही अधिकारियों को अच्छा लगता है और सही भी चाहे तरीका गलत क्यों ना हो, जबकि इस प्रधान आरक्षक को कोई भी ईमानदार अधिकारी पसंद नहीं करता या फिर यह कहा जाए तो उसके विभाग के लोग भी इसे पसंद नहीं करते फिर भी अधिकारियों की चमचागिरी व पावलगी कर अधिकारियों के हितैसी बने रहना उसे खूब आता है।

क्या उच्च अधिकारियों की मनसा में ही नहीं था यह विचार की पुलिसकर्मियों के खिलाफ करनी है कार्यवाही ?

पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है की जब न्यायालय ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और उनके नाम से प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश जारी किया था तब क्यों पुलिसकर्मियों का नाम जिन्हे दोषी माना गया था प्राथमिकी में शामिल नहीं किया गया।क्या पूरे मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों की मनसा ही नहीं थी की वह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जिनके खिलाफ शिकायत थी वह कार्यवाही करें या उन्हे दंडित करें क्योंकि वह दोषी हैं। वैसे पुलिस विभाग में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जब जांच दूसरे की होती है वह जांच में काफी ईमानदार हो जाते हैं वहीं जब मामला पुलिस के ही कर्मियों के दोष से जुड़ा होता है वह उन्हे बचाने में लग जाते हैं। वैसे बैकुंठपुर के मामले में साफ है की पुलिस के उच्च अधिकारी दोषी पुलिसकर्मी को बचाने में अपनी पूरी निष्पक्षता ही हाशिए पर डाल दिए जिससे वह बच सके।

उच्च अधिकारियों ने सिर्फ जांच में पुलिसकर्मियों को बचाने का काम किया ?

बैकुंठपुर के जिस मामले की बात आज यहां की जा रही है उसमे पीड़ित की मौत भी न्याय के इंतजार में हो चुकी है वहीं जिन पुलिसकर्मियों पर बिना आदेश जमीन पर जाकर कब्जा दिलाने का आरोप लगा था जिसे यह माना जा सकता है की वह गुंडागर्दी का मामला था क्योंकि कब्जा दिलाने के लिए पुलिसकर्मियों को कोई निर्देश जारी नहीं था और वह दोषी एक तरह से साबित थे फिर भी उन्हे बचाने जांच के काफी लीपापोती उच्च अधिकारियों के निर्देश पर किया गया। कुल मिलाकर दोषियों को इसलिए बचाया गया क्योंकि वह पुलिसकर्मी थे और वह भी ऐसे जिन्हे उच्च अधिकारियों का हमेशा संरक्षण मिलता रहा है और वह इसी तरह की मनमानी करते रहे हैं।

पुलिसकर्मीयों ने बिना कागज सत्यापन के क्यों गए थे वृद्ध महिला का कब्जा खाली करवाने ?

मामला जिसमे वृद्ध महिला से भूमि कब्जा खाली कराने पहुंचे थे पुलिसकर्मी बैकुंठपुर के उसमे सबसे बड़ा सवाल यह है की बिना कागज सत्यापन के कैसे पहुंचे थे पुलिसकर्मी। क्या वह यह तय करने का इरादा ही नहीं रखते थे की जो कागज उन्हे दिखाया जा रहा है वह सही है या नहीं है या फिर उन्हे कोई बड़ा लालच मिला हुआ था जिस वजह से वह बिना कागज सत्यापन ही पहुंचे थे कब्जा खाली कराने। वैसे बात जो भी हो दोषी थे पुलिसकर्मी तभी न्यायालय ने उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने निर्देश दिया था पुलिस अधिकारियो को जो उन्होंने नही किया और पूरा लीपापोती करते हुए अपने विभाग के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया।

आखिर प्रधान आरक्षक पर कब तक बरसती रहेगी कृपा ?

जिले के सबसे चर्चित प्रधान आरक्षक जिनकी कई बार शिकायतें भी हो चुकी हैं। सत्ता किसी की भी हो अधिकारी कोई भी हो उक्त प्रधान आरक्षक को जहां भी अपनी पदस्थापना लेनी होती है वह लेकर रहता है। विभागीय अधिकारी भी उक्त प्रधान आरक्षक के सामने नतमस्तक हैं और उसके पीछे किसका हांथ है जो अधिकारी भी उसके सामने झुके हुए हैं बड़ा सवाल है। अब सवाल यह भी है की एक प्रधान आरक्षक पर कब तक कृपा बरसती रहेगी। बता दें की कोरिया जिले के जिस प्रधान आरक्षक की बात की जा रही है वह जुगाड लगाने में माहिर है और जिसकी भी सरकार हो वह अपना जुगाड लगा ही लेता है। अब देखना है की भाजपा की नई पारी में भी वह जुगाड लगा पाता है या भाजपा इस बार उक्त प्रधान आरक्षक को तवज्जो नहीं देती है।

बैकुंठपुर थाने में अपराध दर्ज फिर भी पदोन्नति व थान पाने का देखते है सपना

जिले के जिस प्रधान आरक्षक की शिकायतों का अंबार है उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हो पाती? उसके ऊपर बैकुंठपुर कोतवाली में ही अपराध भी दर्ज है। अपराध की जांच लगातार चल रही है क्योंकि पुलिस की जांच पुलिस कर रही है। मामले में प्रधान आरक्षक को बचाने में विभागीय अधिकारी भी उसकी मदद कर रहें हैं। बताया यह भी जा रहा है की खुद के ऊपर अपराध दर्ज होने के बावजूद उक्त प्रधान आरक्षक को अपनी पदोन्नति का इंतजार है जबकि अपराध दर्ज होने की स्थिति में पदोन्नति बाधित की जानी चाहिए। जहां अपराध दर्ज होने के बाद उन्हें पद से पृथक कर देना था वहां आज भी वह पद पर बने हुए हैं स्थिति यह है कि इनके एक ही जिले में रहने से पुलिस की कार्यप्रणाली भी कई मामलों में संदेह के घेरे में रहती है फिर भी उसके ऊपर मेहरबानी क्यों बरसती है यह बड़ा सवाल है अब जब सरकार बदली है सत्ता बदला है तो अब उम्मीद जगी है कि कार्यवाही भी होगी और जिले से इनका बाहर स्थानांतरण भी होगा।

उच्च अधिकारियों तक शिकायत फिर भी आज तक कार्यवाही का इंतजार

प्रधान आरक्षक की कई बार शिकायत भी हो चुकी है। शिकायत के बावजूद कार्यवाही आज तक लंबित है। जिले में आने वाले हर अधिकारी को प्रधान आरक्षक अपनी गिरफ्त में ले लेता है और कार्यवाही से बच निकलता है। अब देखना यह है की जिले में कब कोई पुलिस अधिकारी उक्त प्रधान आरक्षक के संबंध में हुई शिकायत की जांच करता है और निष्पक्ष कार्यवाही करता है। वैसे अभी तक ऐसा कोई पुलिस अधिकारी सामने नहीं आया है और देखना है की अब कोई अधिकारी हिम्मत दिखाता है की नहीं।

प्रधान आरक्षक को अपने ही विभाग के कर्मचारी नहीं करते पसंद

कोरिया जिले के जिस प्रधान आरक्षक की बात की जा रही है उसे जिले के ही पुलिसकर्मी पसन्द नहीं करते। इसके पीछे का कारण यह माना जाता है की वह अपने ही विभाग के कर्मचारियों की शिकायत करता है वह भी झूठी और फिर उसी आधार पर वह अधिकारियों का खास बन जाता है। जिले में कई अच्छे प्रधान आरक्षक और पुलिस कर्मी उसकी वजह से कई बार अधिकारियों की प्रताड़ना का शिकार हो चुके हैं। वैसे प्रधान आरक्षक केवल यही काम भी करते हैं उनका काम अन्य पुलिसकर्मियों पर निगरानी रखना और अधिकारियों तक उनकी चुगली पहुंचाना ही है जिसकी वजह से उन्हे अन्य पुलिसकर्मी पसन्द नहीं करते।

प्रधान आरक्षक को संभाग से बाहर किया जाए इसकी मांग भी लगातार हो रही है...

कोरिया जिले के एक प्रधान आरक्षक को लेकर यह भी मांग होती रही है की उनका तबादला संभाग से बाहर की जाए तभी कई मामलों में उनकी संलिप्तता का खुलासा हो सकेगा। उनका तबादला होगा तभी कई मामले जो उनके विरुद्ध हैं उसकी जांच हो पाएगी। ऐसा कुछ पुलिसकर्मी ही चाहते हैं वहीं कुछ उससे पीड़ित लोग भी चाहते हैं।

क्या प्रधान आरक्षक के रहने से अवैध कारोबारी को मिलता है संरक्षण ?

प्रधान आरक्षक अवैध कारोबारियों को भी संरक्षण देते हैं जिसको लेकर कुछ महीने पूर्व एक ऑडियो भी वायरल हुआ था साथ ही थाने के सामने एक आरोपी के परिजनो से पैस भी लिया गया था जो थाना के सीसीटीवी में कैद हुआ था पर जांचा नहीं हुई,जिसमे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने उन्हे कुछ नहीं किया था। अवैध कारोबारी प्रधान आरक्षक से काफी संपर्क में रहते हैं और यही उन्हे विभाग में उनकी पहुंच का माध्यम बनाते हैं जैसा बताया जाता है। कुल मिलाकर प्रधान आरक्षक पुलिस विभाग की छवि खराब कर रहे हैं और कोरिया पुलिस पर से जनता का विश्वास कम करने का कारण बन रहे हैं। जिस भी मामले में इनका नाम आता है वह मामला खुद व खुद विवादित हो जाता है और मामले में निस्पक्षता समाप्त हो जाती है।

मामला पंजीकृत होने के बावजूद बिना जमानत व बिना विभागीय जांच के पुलिसकर्मी डटे है नौकरी में...यह है पूरा मामला

पुलिस पत्रकार पर या अन्य निर्दोषों पर बिना जांच के मामला पंजीबद्ध तो कर लेती है पर जब खुद इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध होने की बारी आती है तो घबरा जाते हैं फिर बचाव के लिए पूरे पैतरे अजमाने लगते है एक तो इनकी शिकायत हो भी जाए तो इन्ही के अधिकारी इन्हें बचाने लगते है जब की वह भी जानते है की उनका कर्मचारी गलत व दोषी है पुलिस के खिलाफ कितनी भी शिकायत हो जाए यही वजह है कि जांच तो उसी विभाग के अधिकारी को करना है जिस वजह से उन्हें हर बार बच निकलने में सहूलियत होती है, इनके ऊपर तो कार्यवाही तब होती है जब कोई इनके पीछे पड़ जाए उच्च स्तर पर या फिर न्यायालय की शरण ले तब जाकर उसे जीत हासिल हो पाती है पर जीत के आने के बाद ही फिर उसी विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाकर अपने चप्पल घिसने पढ़ते हैं फिर भी राहत नहीं मिलती कुछ ऐसा ही मामला है कुछ सालों पहले का है जहां पर एक व्यक्ति के प्रभाव में पुलिस वाले एक महिला का घर तोड़ने व कब्जा दिलाने के लिए चले जाते हैं उस महिला की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध नहीं होता तब महिला को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है तब वहां पर उच्च न्यायालय मामले में संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध करने तो कहता है जिसके बाद 10 दिन के बाद उस मामले में अपराध पंजीबद्ध होता है पर उस पंजीबद्ध एफआईआर में पुलिसकर्मियों का नाम नहीं होता, वर्ष 2016 में एक महिला की शिकायत पर पुलिसकर्मियों ने मामला पंजीबद्ध नहीं किया तब उसने उच्च न्यायालय शरण लिया लिया था जिसमें उच्च न्यायालय ने 29 नवम्बर 2016 को अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था, जिसमें नामजद अपराध पंजीबद्ध होना था पर पुलिस वाले ही जब अपराध पंजीबद्ध करते हैं तो अपने ही पुलिस वालों का नाम कैसे लिख सकते हैं बिना नाम के ही उन्होंने 9 दिसंबर 2016 को अपराध पंजीबद्ध किया,जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों के नाम की जगह अज्ञात लिख दिया पर सवाल यह है कि हाईकोर्ट के आदेश में सभी के नाम दिए गए थे पर इसके बावजूद पुलिस ने नामजद अपराध दर्ज नहीं किया ना आज तक उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई और ना ही वह पुलिसकर्मी ने जमानत लिया और ना ही विभागीय जांच ही सही से हो पाई, अब समझा जा सकता है कि पुलिसकर्मी यदि करें तो सब सही बाकी के ऊपर पुलिस टूट पड़ती है जबकि संविधान में साफ है कि पुलिसकर्मी भी यदि दोषी हैं तो उन पर भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए पर अक्सर खाकी खाकी की मदद ही करता है और बचने का पूरा प्रयास करता है।

घटती-घटना की मुहिम सहित खबर का हुआ असर...

कोरिया से भारमुक्त होकर सूरजपुर में कार्यभार ग्रहण किया प्रभारी डीपीएम डॉ. प्रिंस जायसवाल ने

18 दिन बाद किया कार्यभार ग्रहण,कोरिया जिला छोड़ने तैयार नहीं थे प्रभारी डिपीएम डॉक्टर प्रिंस जायसवाल

संविदा कर्मचारी होने के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय के आदेश की भी कर रहे थे अवहेलना

सुरजपुर के डीपीएम का तबादला आदेश हुआ संशोधित,उन्हे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर के विकल्प पर भेजा गया जशपुर

कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रभारी डीपीएम का जाना होगा सुखद,जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था आयेगी पटरी पर

घटती-घटना के द्वारा लगातार खबर प्रकाशन की वजह से भारमुक्त हुए डॉक्टर प्रिंस जायसवाल

कोरिया जिले में प्रभारी डीपीएम जिनके ऊपर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को कई बार बेपटरी करने का लग चुका था उनका तबादला दो हफ्ते से भी ज्यादा समय पूर्व सूरजपुर जिले के लिए कर दिया गया था। कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग में दीमक बनकर घर बना चुके डीपीएम फिर भी जिला छोड़कर जाने तैयार नहीं थे। घटती-घटना ने इस विषय में अभियान की तरह अपनी भूमिका निभाई और तब जाकर खबर का असर देखने को मिला और उन्हे भारमुक्त नई पदस्थापना के लिए किया गया। कोरिया जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेपटरी करने के बाद अब वह सूरजपुर जिले पहुंचे हैं वहां वह क्या गुल खिलाते हैं इसपर भी घटती घटना की नजर बनी रहने वाली है,फिलहाल घटती घटना ने डॉक्टर प्रिंस जायसवाल को तबादला आदेश का पालन करने मजबूर किया यह घटती घटना की सफलता रही।

नए जिले में डॉक्टर प्रिंस जायसवाल क्या समय से पहुचेंगे अपने कार्यालय,क्या करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतरी के लिए काम ?

कोरिया जिले में रहते हुए डॉक्टर प्रिंस जायसवाल वेतन लेने के लिए ही शासकीय सेवक थे वहीं अन्य लाभ के लिए ही वह काम किया करते थे,उनका समय जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए तभी मिल पाता था जब उनका लाभ जुड़ा रहता था अन्यथा वह अपने नर्सिंग कॉलेज को ही ज्यादा समय दिया करते थे। कोरिया जिले में स्वास्थ्य विभाग में रहकर उन्होंने अधिकारियों को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था और उन्हे रोकने-टोकने वाला भी कोई नहीं था। अब जब वह नए जिले में कार्य करने पहुंचे हैं क्या वह वहां अपना समय स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए देंगे या वहां भी उनका कोरिया जिले जैसा ही रवैया कायम रहने वाला है। वैसे वह समय से कार्यालय जायेंगे और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभायेंगे यह देखने वाली बात होगी।

-रवि सिंह-
कोरिया/सूरजपुर 12 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

अंततः कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीपीएम डॉक्टर प्रिंस जायसवाल सूरजपुर जिले के लिए भारमुक्त कर दिए गए वहीं उन्होंने सूरजपुर जिले में जाकर कार्यभार ग्रहण भी कर लिया जैसी सूचना प्राप्त हो रही है। डॉक्टर प्रिंस जायसवाल विगत 18 दिनों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय के आदेश को ठेंगा दिखाने का प्रयास कर रहे थे और कोरिया जिला छोड़कर वह जाना नहीं चाह रहे थे वहीं अब उन्हे जिले से जाना पड़ा और नई जगह पदभार ग्रहण करना पड़ा। डॉक्टर प्रिंस जायसवाल जो कोरिया जिले के प्रभारी डीपीएम थे विगत वर्षों से या यह कहें कांग्रेस शासनकाल से ही उन्हे वर्तमान भाजपा सरकार ने सूरजपुर का डीपीएम बनाया और सूरजपुर भेजा वहीं सूरजपुर के डीपीएम को कोरिया जिले का डीपीएम साथ साथ बनाया।

कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे डीपीएम सूरजपुर जाना नहीं चाह रहे थे वहीं बताया जाता है की कोरिया जिले में चौपट हो चुकी एन एच एम विभाग की कार्यशैली की वजह से सूरजपुर के

डीपीएम आदेश के बाद भी कोरिया जिला आना नहीं चाह रहे थे। इसी का फायदा डॉक्टर प्रिंस जायसवाल भी उठा रहे थे और नए डीपीएम के कार्यभार नहीं करने का बहाना बनाकर वह भी भारमुक्त होने से बच रहे थे। इसी बीच सूरजपुर जिले के डीपीएम को जशपुर मुख्य चिकत्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी के विकल्प पर भेज दिया गया जिसके बाद डॉक्टर प्रिंस जायसवाल को सूरजपुर जिले में कोरिया जिले से भारमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करना पड़ा। इस बीच घटती घटना ने एक मुहिम एक अभियान के तहत इस खबर का प्रकाशन जारी रखा जिससे प्रभारी डीपीएम कोरिया जल्द से जल्द भारमुक्त हों जिले से और जिसके बाद कोरिया जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। घटती घटना ने कई बार इस विषय में समाचार का प्रकाशन कर प्रयास जारी रखा प्रभारी डीपीएम कोरिया डॉक्टर प्रिंस जायसवाल के विभाग में खासकर कोरिया जिले में उनके जारी भ्रष्टाचार को भी उजागर करने का काम घटती घटना ने जारी रखा और अंततः उनका कोरिया जिले से पलायन हो सका। वैसे बताया जा रहा है की वह कोरिया जिला छोड़ने बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उन्हे अपने नर्सिंग कॉलेज की ज्यादा चिंता सताती है जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था जिसके लिए वह शासन से वेतन और सम्मान पाते हैं वह उनके लिए एक अतिरिक्त समय पर किया जाने वाला काम है और वही वह करते हैं। डॉक्टर प्रिंस जायसवाल अपनी पूरी क्षमता और पूरी प्रशासनिक पकड़ विभागीय सभी सहूलियत केवल नर्सिंग कॉलेज को उनके मिलता रहे इसी में दिमाग लगाते आते रहे।

नए जिले में भी क्या अधिकारियों को कर लेंगे अपने वश में...क्या वहां भी कर सकेंगे मनमानी ?

डॉक्टर प्रिंस जायसवाल एक मामले में काफी होनहार और योग्य हैं और वह योग्यता है बड़े नेताओं मंत्रियो से रिश्तेदारी साबित कर अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी करना,कोरिया जिले में जब वह कार्यरत थे तब उनके कार्यकाल के ही दौरान कांग्रेस सत्ता में थी तब वह कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार बनकर अधिकारियों पर दबाव बनाते थे अपनी मनमानी करते थे वहीं सत्ता बदलते ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से ही रिश्तेदारी का ऐलान कर दिया,अब देखना है की उनकी कुल योग्यता और उनकी सफलता का असली राज जो नेताओं को करीबी रिश्तेदार बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाना है वैसा ही वह नए जिले में कर पाते हैं और सफल हो पाते हैं। वैसे उनकी इस काबलीयत को छोड़कर अन्य पर सभी को संदेह रहता है।

क्या कोरिया जिले में उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार सहित उनके खिलाफ हुई शिकायतों की होगी निष्पक्ष जांच ?

डॉक्टर प्रिंस जायसवाल से कोरिया जिले के स्वास्थ्य विभाग को एक तरह से छुट्टी मिल सकी। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था खासकर एनएचएम में भारी भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ है जिसमे खरीदी भर्ती सहित वाहन किराया मामले में फर्जीवाड़ा शामिल है। कोराना महामारी काल में भी इन्होंने आपदा को अवसर बनाया था और तब भी कई शिकायत सामने आई थी। नर्सिंग कॉलेज जिसका यह संचालन करते हैं उसकी भी शिकायत समाने आती रही है। सभी मामलों में यह केवल इसलिए बचते आ रहे थे क्योंकि यह जिले में ही कार्यरत थे और मामले को दबा ले जाते थे। अब जबकि उनका तबादला हो चुका है देखने वाली बात होगी की क्या अब उनके मामलो में जांच होगी।

जिला औषधि विक्रेता संघ का चुनाव संपन्न

-संवाददाता-
सूरजपुर,12 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

सोमवार को स्थानीय साधुराम सेवा कुंज में जिला औषधि विक्रेता संघ का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में भारी गहमा-गहमी के बीच जिले के दवा विक्रेताओं के द्वारा किए गए मतदान के बीच केमिस्ट एकता पैनल ने विजय श्री हासिल करते हुए अध्यक्ष व सचिव सहित कोषाध्यक्ष के पद पर एक तरफा जीत दर्ज की है। पैनल के विनोद अग्रवाल ने अध्यक्ष, अमूल्य चंद्रा ने सचिव व राजेश कुमार जायसवाल ने कोषाध्यक्ष के लिए जीत परचम लहराया है। वही एकता पेनल के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि एक अन्य उम्मीदवार भी अध्यक्ष पद पर अपराजित रहे। उल्लेखनीय है की सूरजपुर जिला औषधि विक्रेता संघ का चुनाव जिला मुख्यालय के हीरालाल साधुराम सेवाकुंज में चुनाव अधिकारी रमाशंकर कुशवाहा अम्बिकापुर की उपस्थित में संपन्न हुआ। सांगठनिक चुनाव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से सुभाष गोयल अम्बिकापुर व प्रदेश कार्यकारिणी से अजय अग्रवाल रायगढ़ पर्यवेक्षक के रूप में विशेष रूप से पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित थे। विदित हो कि सूरजपुर जिला औषधि विक्रेता संघ के चुनाव में केमिस्ट एकता पेनल व एकता पेनल के बीच अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के पद को लेकर सीधा मुकाबला था। जिसमें केमिस्ट एकता पेनल से अध्यक्ष के लिए विनोद अग्रवाल, सचिव के लिए अमूल्य चंद्रा तथा कोषाध्यक्ष के लिए राजेश जायसवाल उम्मीदवार थे। वहीं एकता पेनल की ओर से अध्यक्ष पद के लिए अनुज राजवाड़े, सचिव पद के लिए विकास अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए पवन गर्ग मैदान में थे। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए अन्य उमीदवार में सुरेश मित्तल भी पृथक से इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे थे। जिले के 264 पंजीकृत दवा विक्रेताओं के संघ में पूरे जिले के 246 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सूरजपुर जिला औषधि विक्रेता संघ के नए सत्र के पदाधिकारी का चुनाव किया। जिसमें अध्यक्ष पद के लिए विनोद अग्रवाल को 192, अनुज कुमार राजवाड़े 45 व सुरेश मित्तल को 09 मत मिले। सचिव के लिए हुए मतदान में अमूल्य चंद्रा को 159 तथा विकास अग्रवाल को 84 तथा कोषाध्यक्ष में राजेश कुमार जायसवाल को 172 व पवन गर्ग को 73 मत प्राप्त हुए। संगठन चुनाव के उपरांत संघ के सभी सभी सद सदस्यों ने पदाधिकारियों को बधाई दी। वही निर्वाचन अधिकारी सहित पंवेक्षको ने भी औषधि विक्रेता संघ को नये सत्र की नई कार्यकारिणी व वार्षिक सम्मेलन की बधाई दी। इस दौरान राजेश जायसवाल,राजेश गोयल, दीपक मित्तल, अरविंद जायसवाल, नवीन अग्रवाल, मुकूल तायल, राजेश अग्रवाल, राजेश जायसवाल, मोहित अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, ब्रहमदेव मोदी, बाबूलाल अग्रवाल, जमाल हसन, रूपेश पांडे, राकेश कुमार, नवीन, नितीन, राजेश्वर गुप्ता सहित संघ के सदस्य कार्यक्रम सक्रिय थे।

सबसे चुनौतीपूर्ण होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिन का काम : डॉ सरोज पांडेय

-संवाददाता-
कोरबा,12 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग के तत्वावधान में मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन राजीव गांधी ऑडिटोरियम कोरबा में आयोजित किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोरबा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉ सरोज पांडेय रही। कार्यक्रम का सुभारम्भ मितानिनो के द्वारा स्वागत गीत एवं फाग गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम में जिलेभर आई मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हुजूम को देख स्वयं डॉ सरोज पांडेय ने मंच से उतरकर व्यवस्था बनाई।

महिलाओं को सम्बोधित करते हुए डॉ सरोज पांडेय ने कहा कि जहां दूर-दराज स्थानों पर कोई जहाँ पाता वहां मितानिन व आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता पहुँचती है, सुबह से लेकर शाम तक उनका काम अत्यंत ही कठिन व चुनौतियों से भरा होता है। सरकार की योजनाओं और सर्वे को जमीन तक ले जाने का कार्य करती है। प्रसव, बीमारी, टीकाकरण आदि कार्यों में इनकी सेवाभवना अद्भुत है। आज उनके सेवा कार्यों का ही सम्मान हो रहा है।डॉ पांडेय ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी निरंतर महिलाओं की चिंता करते रहते है। वे लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पीएम आवास, शौचालय, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, लखपति दीदी एवं ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं लाए है। उन्होंने सभी महिलाओं से केन्द्र एवं राज्य सरकार को योजनाओं का लाभ लेने कि बात कही। सुश्री पांडेय ने कहा कि मितानिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान देखा कि मितानिनो के लिए स्थाई भवन अति आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आगामी समय मे कोरबा लोकसभा में हर कुछ दूरी पर मितानिन भवन बनाया जाएगा।साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिनों की लंबित मांगो को भी पूरा करवाने का भरपूर प्रयास करेंगी। उन्होंने उपस्थित सभी महिलाओं को आगामी तीज पूर्व एकसाथ मनाने का भी निमंत्रण दिया।

बटन दबाकर वादा किया पूरा धान की अंतर राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचा

-संवाददाता-
प्रतापपुर 12 मार्च 2024
(घटती-घटना)।

कृषक उन्नति योजना 2023 आदान सहायता राशि वितरण एवं किसान मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुई क्षेत्रीय विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास कल्याण संघ एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतापपुर के मंगल भवन में धान बोनस वितरण का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल उद्घाटन बटन दबाकर किया गया जिसमें स्थानीय विधायक सम्मिलित हुई एवं अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह काम यथार्थ में करके दिखाती है जब से विष्णु देव साय मुख्यमंत्री बने हैं तब से आम जनता को लगातार कुछ ना कुछ लाभ मिलते जा रहा है चाहे गैस सिलेंडर हो , मातृ वंदन योजना हो, धान बोनस , पांच सौ पचपन रुपए प्रति सैकड़ा तेंदूपत्ता का हो। उन्होंने आगे कहा कि आप जनता जनार्दन व देवतुल्य कार्यकर्ताओं के वजह से ही यह शुभ अवसर देखने को मिला है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लाल संतोष सिंह, एसडीएम ललिता भगत,अजीत शरण सिंह, अक्षय तिवारी, अवधेश पांडे, शरद चंद्र द्विवेदी, विनोद जायसवाल, विक्रम नामदेव, अवधेश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, थाउला राम, विजेंद्र कश्यप, लक्ष्मी गुप्ता, अनुराग द्विवेदी, गुलाब मोहन तिवारी, शिव शंकर यादव, एच आर पात्रे , सचिन तायल, विकास तिवारी, चंद्रिका यादव, शहादत हुसैन, वेद प्रकाश गुप्ता, अभिषेक सिंह, मनहरण लाल बंजारे,अशोक जायसवाल, आभा शुक्ला, गोपाल शरण सिंह, अभिषेक गुप्ता, मुकेश गुप्ता, जितेंद्र यादव किसान एवं सरकारी कर्मचारी व भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202403020700047

विषयः-अ-6 मामले की श्रेणीः-राजस्व सनः 2023-2024

सपना प.ह.न. 00028 [हे0)]
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार- परिता,
अनोवदक पक्षकार - धीरन

ईश्तहार

आवेदक परिता पति राम दास,निवासी ग्राम सपना, तहसील अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम सपना स्थित खसरा नंबर 590/1 रकबा 0.138 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों से मृत भूमि स्वामी स्व0 धीरन का नाम विलोपित कर पैती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 27/03/2024 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थि होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 04/03/2024 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202403020700017

विषयः-अ-6 मामले की श्रेणीः-राजस्व सनः 2023-2024

नवागढ़ प.ह.न. 00013 [हे0)]
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार- अब्दुल लतीफ
अनोवदक पक्षकार - अब्दुल रउफ पिता

ईश्तहार

आवेदक लतीफ आ0 स्व0 हाजी अब्दुल रउफ निवासी खरसिया रोड, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम नवागढ़ स्थित खसरा नंर 205/10 रकबा 0.049 हे0 भूमि को वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 18/03/2024 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थि होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01/02/2024 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

(सार्वजनिक उद्घोषणा)

क्रं0/क्यू/वाचक/2/2024 दिनांक 12.3.024

सर्व साधारण ग्राम जोबगा तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर छ0ग0 को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक मनमोहन सिंह पिता भदर सिंह जाति गोड़ निवासी ग्राम जोबगा तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0 के द्वारा अपने भाई महेन्द्र सिंह पिता भदर सिंह का जन्म दिनांक 03/09/2021 होने से जन्म प्रमाण पत्र हेतु स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म) रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) नियम 1973 के नियम 10(3) के अंतर्गत निदेष देने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गय गया है। जिस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

इस संबंध में जिस किसी व्यति या संस्था को कोई आछेप(आपत्ति हो तो दिनांक 19/03/2024 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आछेप/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। तदानुसार प्रकरण में कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक / /2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पद मुद्रा से जारी।

सील — तहसीलदार, सूरजपुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /अ-6/2023-24

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सरदार कृपाल सिंह, आ0 सरदार त्रिलोक सिंह, निवासी-मायापुर गुरूद्वारा वार्ड अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-कौआडांड, नगर-अम्बिकापुर स्थित नजूल भूमि शीट नं0-03 मोहल्ला-कौआडांड, नगर-अम्बिकापुर स्थित नजूल भू-खण्ड क्रमांक 1536 में से रकबा क्रमशः 0.08 एकड भूमि को अनावेदक/दानदाता सरदार सुरजीत सिंह, आ0 सरदार त्रिलोक सिंह, उम्र-50 वर्ष, निवासी-मायापुर गुरूद्वारा वार्ड, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा से पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 22.02.2024 के माध्यम से प्राप्त किया है। उक्त नजूल भूमि के अभिलेखों में आवेदक का नाम पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 109,110, छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 27/03/2024 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 28/02/2024 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार नजूल, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

रा.प्र.क्र. 1301/अ-20(1)/2023-24

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है छत्तीसगढ़ शासन राजस्व प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 04-07/सात-01/2019 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11/09/2019 के द्वारा जारी निर्देशानुसार छ0ग0 राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड 4(1) एवं 4(2) के अद्यतन संशोधित प्रावधानों के तहत आवेदक अनुप कुमार तिर्की, अरूण कुमार तिर्की आ0 प्रमोद तिर्की निवासी मोहल्ला मुक्तिपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा नगर अम्बिकापुर के मोहल्ला/ग्राम मुक्तिपारा, अम्बिकापुर स्थित शासकीय नजूल भूमि भूखण्ड क्रमांक 120/1 रकबा 38.96 एकड़ में से रकबा 187.72 वर्गमीटर भूमि पर शीटयुक्त मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। उसके व्यवस्थापन/आबंटन वावत आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 28/03/2024 तक न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — तहसीलदार नजूल अम्बिकापुर

CMYK

प्रधानमंत्री ने दिया 85 हजार करोड़ रूपये से अधिक की सौगात

राज्यपाल हरिचंदन और मुख्यमंत्री श्री साय की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ को डेढ़ सौ करोड़ रूपये लागत के 43 रेल परियोजनाओं की सौगात भी मिली

- देश को समृद्ध और विकसित बनाने में रेलों की महत्वपूर्ण भूमिका...
- आने वाले समय में और तेज होगा रेल आधुनिकीकरण का काम : प्रधानमंत्री श्री मोदी
- देश को समृद्ध और विकसित बनाने में रेलों की महत्वपूर्ण भूमिका...
- प्रधानमंत्री ने किया 85 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लगभग छह हजार रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास...

रायपुर,12 मार्च 2024 (ए)। प्रधानमंत्री ने किया 85 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लगभग छह हजार रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया 85 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लगभग छह हजार रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया 85 हजार करोड़ रूपये से अधिक की लगभग छह हजार रेल परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए देश वासियों के लिए 85 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक लागत की लगभग छह हजार छोटी-बड़ी रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। रेलवे के बुनियादी ढांचा विकास की इन परियोजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ार्म एक पर हुए कार्यक्रम में लगभग 670 से अधिक रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों से भी वीडियो कॉफ्रेंसिंग द्वारा लोग शामिल हुए। राज्यपाल हरिचंदन और मुख्यमंत्री साय ने स्थानीय कार्यक्रम में रायपुर मण्डल की रेल विकास परियोजनाओं के शिलालेखों से पर्दा हटाकर औपचारिक अनावरण किया। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू राजेश मूणत और ज़िला तथा रेल प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद कमांड सेंटर से हरी झंडी दिखाकर 10 नई वंदे भारत रेल गाडिय़ों को भी रवाना किया।

हमनें भारतीय रेल को नरक जैसी स्थिति से बाहर निकालने की इच्छा शक्ति दिखाई : श्री मोदी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पिछले 100 वर्षों में भी एक कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में रेल परियोजनाओं के शुभारंभ का कार्यक्रम आज पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि इस नये साल के पिछले 75 दिनों में ही देश में 11 लाख करोड़ रूपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। उन्होंने इसे विकसित भारत की दिशा में देश का एक बड़ा कदम बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे लंबे समय से राजनीति और क्षेत्रवाद का शिकार रही है। रेलों में डब्बे बढ़ाना, स्टॉपेज बढ़ाना ही रेल की प्रगति के मायने रहें थे। बीते समय में रिजर्वेशन की लंबी लाईनें, दलाली और कमिशन के साथ गंदगी ने भारतीय रेल की स्थिति नरकीय बना दी थी। वर्ष 2014 में देश के 9 राज्यों की राजधानियां रेल नेटवर्क से अछूती थी। 10 हजार से अधिक रेल क्रॉसिंग फाटक विहीन थी। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने भारतीय रेल को नरक जैसी स्थिति से बाहर लाने की इच्छा शक्ति दिखाई है। रेवले के बजट को समान्य बजट के साथ शामिल कर छह गुना बढ़ाया गया है। इससे दूसरे मदों से मिले राजस्व का हिस्सा भी रेलवे के विकास के लिए उपयोग किया जा सका है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में भारतीय रेलवे का ऐसा कायाकल्प होगा कि किसी ने भी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बुजुर्गों और हमनें जो भुगता है वो आने वाली पीढ़ी नहीं सहेगी, यह मोदी की गारंटी है।

हमारे विकास के काम राजनीतिक रूप से सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश बनाने के लिएः प्रधानमंत्री मोदी

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को समृद्ध और औद्योगिक रूप से विकसित करने में रेल की बहुत बड़ी भूमिका है। सवारी गाडिय़ों और माल गाडिय़ों के लिए अलग-अलग रेल लाईनें स्थापित कर दोनों की स्पीड बढ़ाई गई है। फ्रंट कॉरीडोर बनाकर तेजी से डबल डेकर माल गाडिय़ों से माल ढुलाई शुरू हो गई है। आधुनिक रेल इंजन, सुसज्जित कोच फैक्ट्रियां, गति शक्ति कार्बो टर्मिनल जैसी अधोसंरचनाएं भारत को विकसित बनाने की दिशा में तेजी से सकारात्मक योगदान दे रहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना आधुनिक तकनीक पर लोकोमोटिव इंजन निर्माण से लेकर नई पटरियां बिछाने, स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसे अनेकों काम देश में हुए है। हमारे देश में बने लोकोमोटिव श्रीलंका सुडान, मोजाबिंक जैसे देशों को निर्यात किए जा रहें है। हम सौर उर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहें है। स्टेशनों पर जल औषधी केन्द्र खोल रहें है, स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और स्व-सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए स्थानीय शिल्प और कलाकृतियों को स्टेशनों पर बिक्री के लिए स्टॉल खोले जा रहें है। जिसका लाभ सीधे गरीब कारीगरों को मिल रहा हैं। रेलवे में आधुनिक तकनिकों के उपयोग से देश के कोने-कोने को रेल नेटवर्क से जोडऩे का काम तो हो ही रहा है इसके साथ ही नये निवेश की गारंटी भी मिल रही है और रोजगार के अवसर भी खुल रहें है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विकास के काम राजनीतिक रूप से सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश बनाने के लिए है।

रेलवे में अधोसंरचना विकास से रोजगार सृजन के भी बन रहे अवसरः राज्यपाल हरिचंदन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे विकास के राजमार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। वन्दे भारत ट्रेनों का चलना और अमृत स्टेशनों का निर्माण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है। रेलवे के विकास का सीधा प्रभाव देश के विकास पर होता है। भारतीय रेलवे अपनी अधोसंरचना में तेजी से सुधार करते हुए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है। प्रमुख स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों के लिए स्टॉल, रेल कोच रेस्टोरेंट तथा जन औषधि केन्द्र खोलकर कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिल रहें है। इन केन्द्रों से वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय स्वदेशी उत्पादों का बाजार उपलब्ध कराने और कुम्हारों, बुनकरों जैसे स्थानीय शिल्पकारों को अजीविका के अवसर देने के साधन भी यह केन्द्र बन रहें है। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ को लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपये की रेल परियोजनाओं की सौगात देने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया।

छत्तीसगढ़ के स्टेशनों में सुविधा विस्तार और रेल परियोजनाओं से लोगों को मिलेंगे रोजगार के अवसर : मुख्यमंत्री श्री साय

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन देश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी एतिहासिक है। 85 हजार करोड़ रूपये से अधिक के रेल परियोजनाओं के लिए श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिक्री केन्द्रों का शुभारंभ करने और जांजगीर-नैला तथा पेंड्रा रोड स्टेशन पर जन औषधि केन्द्र खोलने के साथ अन्य दूसरे विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आशा की कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की नए सोपान गढ़े जाएंगे जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बेहतर अवसर मिलेंगे।आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में भी लगभग 150 करोड़ रूपये की 43 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में 124 करोड़ रूपये की लागत वाली 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और 125 करोड़ रूपये की लागत वाली 3 परियोजनाओं की आधार शिला रखी। छत्तीसगढ़ में वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर रेल मण्डल के रायपुर, मांढर, मंदिर हसौद, तिल्दा-नेवरा, सरोना और उरकुरा रेलवे स्टेशनों सहित राज्य के 18 स्टेशनों पर 34 स्टॉलों का लोकार्पण किया गया। जांजगीर-नैला और पेण्ड्रा रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केन्द्र, दुर्ग कोचिंग डिपो में पीटलाईन का उन्नयन, बिलासपुर में रेल कोच रेस्टोरेंट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री ने किया। मोदी ने बिलासपुर में वन्दे भारत मेंटनेंस डिपो, भिलाई में मेमू कार शैड विस्तार, अंबिकापुर मे नई पीटलाईन निर्माण का शिलान्यास भी किया।

पीएम मोदी ने 10 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद से कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इसमें 10 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे 41 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहा है. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम भूपेन्द्र पटेल और राज्य भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल भी मौजूद रहे।
शिलान्यास के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी ही रेलवे की पटरी पर शुरू की है. यह 10 साल का काम तो अभी ट्रेलर है, मुझे और आगे जाना है । आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी, उनके कार्यकाल में रेलवे का विकास नहीं हुआ । पहले की सरकारों के साथ रेल प्राथमिकता में नहीं था।

रेलवे का कायाकल्प ही विकसित भारत की गारंटी

पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अगले पांच साल में रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा. पहले रेलवे रिजर्वेशन में दलाली होती थी, कमीशनखोरी का खेल होता था, लेकिन अब सब बंद हो गया है. रेलवे का कायाकल्प ही विकसित भारत की गारंटी है। देखें नई वंदे भारत ट्रेन का रूट्स नई ट्रेनों के साथ ही अब दिल्ली सबसे अधिक संख्या में वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने वाला शहर बन गया है. इसमें 10 ट्रेनें राजधानी में समाप्त होंगी. ये ट्रेनें दिल्ली को देहरादून, अंब अंदौरा, भोपाल, अयोध्या, अमृतसर और अब खजुराहो जैसे विभिन्न गंतव्यों से जोड़ती हैं।

संक्षिप्त खबरें

अमरेश मिश्रा बने एसीबी और ईओडब्ल्यू के आईजी

रायपुर,12 मार्च 2024(ए)। राज्य शासन द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमरेश मिश्रा ,महानिरीक्षक रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो,रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया

आरएनएस के वरिष्ठ पत्रकार पंकज स्वामी का निधन

रायपुर,12 मार्च 2024 (ए)। राष्ट्रीय न्यूज सर्विस के वरिष्ठ पत्रकार पंकज स्वामी निवासी जबलपुर मध्यप्रदेश का आज सुबह साढ़े 6 बजे जबलपुर में निधन हो गया।

वनवासियों के लिए विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा

- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बटन दबाकर किया कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ
- जिले के डे लाख से अधिक किसानों के खाते में 799 करोड़ 66 लाख रुपये अन्तरित
- किसानों को सबसे ज्यादा आदान सहायता राशि देने का काम कर रही हमारी सरकारः राजस्व मंत्री श्री वर्मा
- राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा कृषक उन्नति योजना के शुभारंभ एवं आदान सहायता राशि अंतरण कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर,12 मार्च 2024(ए)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ एवं आदान सहायता राशि का अंतरण बालोद जिले में आयोजित कार्यक्रम में किया। कृषक उन्नति योजना के तहत जिले के 1 लाख 56 हजार 713 किसानों के बैंक खाते में लगभग 799 करोड 66 लाख रुपये डीबीटी के माध्यम से आदान सहायता राशि का अंतरण किया गया। बलौदाबाजार स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुख्य कार्यक्रम से जिला मुख्यालय एवं जनपद मुख्याल वर्चुअली जुड़े थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण है जिसमे किसानों को आदान सहायता के रूप में बड़ी राशि का अंतरण किया गया है। किसानों में उत्साह और खुशी का माहौल है। किसानों की चिंता करते हुए हमारी सरकार ने मोदी की गारण्टी के तहत एक और गारण्टी पूरी की है। इस गारण्टी के पूरे होने से अब किसानों को आदान सहायता राशि देने में हमारी सरकार सबसे आगे है। पूरे प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले10 मार्च को ही प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खाते में एक- एक हजार रुपये महतारी वंदन योजना की पहली किश्त का अंतरण किया गया है। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों को सम्मानित व पुरस्कृत करने के लिए फिर से खेल अलंकरण समारोह की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने तथा विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सबकी सहभगिता जरूरी है।

विधायक देवेंद्र यादव को झटका

गिरफ्तारी से बचने दायर की गई याचिका खारिज

बिलासपुर,12 मार्च 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले के आरोपी भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की बेंच में हुई। इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने देवेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी , लेकिन उस जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया गया है।
पिछली सुनवाई में विधायक दवेन्द्र के वकील ने तर्क देते हुए कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा, उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस के आरोपी को केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि, वो सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और ईडी की जांच में मिले साक्ष्यों को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

प्रदेश कांग्रेस ने ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर की नियुक्तियां

रायपुर,12 मार्च 2024(ए)। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष समेत संगठन के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की है। इस संबंध में संगठन प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू ने आदेश जारी किया है. जिसमें दो ब्लॉक अध्यक्ष, समस्या निवारण प्रकोष्ठ, लोककला एवं सास्कृतिक प्रकोष्ठ, विकलांग सेवा प्रकोष्ठ में नियुक्तियां की है.।

किम्सी जैन के बाद हाईकोर्ट से दो और अभियुक्त दोषमुक्त

रायपुर/बिलासपुर,12 मार्च 2024 (ए)। शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर आईपी मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा मर्डर केस में हाई कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साल 2015 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में हाई कोर्ट ने किम्सी जैन के पति विकास जैन और चाचा अजीत सिंह को बरी कर दिया है।
फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच ने 5 दिसंबर 2023 की अंतिम बहस के बाद सुरक्षित कर लिया था। आज इस प्रकरण पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने किम्सी कंबोज के पति और चाचा को भी बरी कर दिया है।मामले में किम्सी कम्बोज पहले ही साल 2021 में रिहा हो चुकी है। क्योंकि पुलिस ने किम्सी को संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया था, लेकिन अभियोजन पक्ष किम्सी को आरोपी सिद्ध नहीं कर सका। वहीं जिला न्यायालय दुर्ग में न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की कोर्ट ने किम्सी के पति विकास जैन और चाचा अजीत सिंह को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
इस बात को लेकर अभियुक्त पक्ष यानी किम्सी कंबोज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका में तीन साल सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच ने समाप्त करते हुए आज अपना फैसला सुनाया है।

यह बना प्रकरण और बरी होने का कारण

अभियोजन पक्ष यानी शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर आईपी मिश्रा ने भी ने किम्सी कंबोज को बरी करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद अब अभियोजन पक्ष को आईपी मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा है।
वहीं बचाव पक्ष की ओर से दुर्ग जिला न्यायालय की अधिवक्ता उमा भारती साहू ने अपनी पैरवी से आईपी मिश्रा के वकील की सभी दलिलो का जवाब दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस और अभीयोजन पक्ष के अधिवक्ता की ओर से सिर्फ कॉल डिटेल सीडीआर के आधार पर अभियुक्त को आरोपी नहीं बनाया जा सकता।
आरोपी ने मृतक से फोन पर बात की है यह साबित किया गया, लेकिन क्या बात हुई, यह अभियोजन साबित नहीं कर सका। सिर्फ सीडीआर डिटेल के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता। जिसके दुर्ग जिला न्यायालय के आजीवन कारावास की सजा को समाप्त करते हुए उच्च न्यायालय ने विकास जैन और अजीत सिंह को रिहा करने का फैसला सुनाया।

ये है पूरा हाई प्रोफाइल कत्ल का किस्सा

साल 2015 में भिलाई के स्मृति नगर में सामने आई थी. जब नवंबर 2015 में अभिषेक मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। 10 नवंबर 2015 की शाम शंकराचार्य इंजीनियरिंग मेडिकल के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण कर हत्या कर दिया गया था।इस किडनैपिंग की खबर ने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी थी। इसकी सूचना केंद्रीय मंत्रियों तक भी पहुँची, जिसके बाद पुलिस पर आरोपियों को पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। पुलिस ने इसे सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यही वजह थी कि पूरे देश के करीब एक करोड़ मोबाइल कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस को भिलाई के सेक्टर-10 निवासी विकास जैन पर संदेह हुआ। घटना के करीब 45 दिन बाद आरोपी विकास जैन के चाचा अजीत सिंह के स्मृति नगर निवास के बगीचे में दफन की गई अभिषेक मिश्रा की सड़ी गली लाश बरामद हुई। आरोपियों ने बेहद ही शातिराना अंदाज में लाश को दफना कर ऊपर फूल गोभी की सब्जियां उगा दी थी। पुलिस ने लाश के पास हाथ का कड़ा, अंगूठी और लॉकेट देखकर अभिषेक का शव होने की पुष्टि की थी। लाश का ष्ठह्व टेस्ट भी कराया गया था. इस मामले में कॉल डिटेल के आधार पर किम्सी कंबोज, विकास जैन और अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

कुख्यात डकैत चंदन सिंह गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर,12 मार्च 2024 (ए)। बिहार में कई गंभीर और संगीन अपराधों को अंजाम देने के बाद कुख्यात डकैत चंदन सिंह दुर्ग में एक किराए के मकान में छिपकर रहता था। आधी रात को पहुंची बिहार पुलिस ने दुर्ग पहुंचकर मोहननगर थाना पुलिस की मदद से आरोपी को दबोच लिया।सूत्रों ने बताया कि दुर्ग पुलिस लगातार वारंटियों /अपराधियों की धरपकड़ अभियान चला रही है। कुख्यात आरोपी चंदन सिंह की तलाश बिहार पुलिस कर रही थी और उसे तलाशते हुए बिहार एसटीएफ को टीम रविवार शाम दुर्ग पहुंची थी। इसके बाद दुर्ग पुलिस से संपर्क किया। जिस पर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने डीएसपी आकांक्षा पांडेय के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इसके बाद आधी रात 12.30 बजे हरि नगर के एक मकान में दबिश दी गई। वहां से पुलिस ने आरोपी चंदन सिंह को धरदबोचा। जानकारी के अनुसार बिहार के रहने वाले चंदन सिंह पर दरौदा एमएच नगर थाना में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। जिसमें मुख्य रूप से उसके वर्ष 2014, 2017 में हत्या का मामला है। वर्तमान में आरोपी चंदन सिंह पर छपरा के किसी कांट्रेक्टर से रंगदारी मांगने का आरोप है। बताया जाता है कि कुख्यात आरोपी चंदन सिंह के खिलाफ बिहार में आधा दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है। जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट डकैती ,एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर मामले शामिल है।

छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी मॉडल

आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन

राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने अयोध्या स्थित भव्य मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरु की। राज्य में राजिम कुंभ (कल्प) का भव्य आयोजन पुन: शुरु कर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे वैश्विक पहचान दी है। इसी तरह धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में पांच शक्तिपीठों को विकसित करने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1 हजार किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। राज्य की रामायण मंडलियों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के साथ बस्तर दशहरे को 50 लाख, चित्रकोट के लिए 10 लाख की जगह 25 लाख रुपये, रामाराम मेले के लिए 15 लाख रुपये तथा गोंचा पर्व के लिए 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को इसी बात से परखा जा सकता है कि सरकार के गठन के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहली कैबिनेट में विष्णु देव साय सरकार ने 18 लाख 12,743 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया। योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि का भी प्रावधान किया गया। वर्तमान में लगभग 15 लाख आवास के निर्माण को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विकास का सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी मॉडल देखने को मिल रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस नीति

विष्णु देव साय सरकार एक ओर सुशासन की दिशा में नीतिगत कदम उठा रही है, वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अमल में ला रही है। पूर्ववर्ती सरकार में हुए पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। साथ ही EWO द्वारा भी इस घोटाले में जांच की जाएगी है। कोयला और शराब घोटाले में भी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस तरह सरकार भ्रष्टाचार ख़त्म करने का प्रयास कर रही है।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वय पर जोर

सुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरु किया गया।

अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का अंत्योदय

पं.दीनदयाल उपाध्याय ने सुशासन को अंत्योदय का आधार बताया है। इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए राज्य में सुशासन एवं अभिसरण विभाग नाम से एक नया विभाग गठित किया गया है। यह विभाग राज्य में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन व संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन करेगा। सरकारी योजनाओं की निगरानी तथा समीक्षा के लिए सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरु किया गया।

विकास के 10 स्तंभों की संकल्पना

विष्णु देव साय सरकार ने अपने पहले बजट में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को 10 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक ले जाने का रोडमैप प्रस्तुत किया है। 1 नवंबर 2024 को राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सरकार के विजन डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करेगी। इसमें 2047 तक छत्तीसगढ़ की तरक्की की कार्ययोजना का विस्तृत वर्णन होगा। राज्य सरकार ने बजट में प्रदेश के अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ चिन्हित किए हैं।

अर्थतंत्र को गति देने के दस स्तंभ

1. ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था
2. तकनीक आधारित सुधार व सुशासन
3. आधिकारिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाना
4. प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन
5. सेवा क्षेत्र को बढ़ावा
6. निजी निवेश
7. बस्तर-सरगुजा की ओर देखो नीति
8. डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स का विकास
9. छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहन
10. योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन

विष्णु देव सरकार... 13 दिसंबर को ली शपथ और छत्तीसगढ़ में चल पड़ा विकास का सिलसिला

13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में खुशियों का नया सूर्योदय हुआ। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की कैबिनेट के शपथ ग्रहण के साथ ही प्रदेश में विकास का सिलसिला चल पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए त्वरित और पारदर्शी निर्णयों से विष्णुदेव साय सरकार ने सुशासन को नया आयाम दिया है। किसान, युवा, महिला, गरीब, आदिवासी सहित सभी तबकों तक विकास की बयार पहुंच रही है।

मोदी की गारंटी
सुशासन के तीन माह

युवा हितैषी सरकार

प्रदेश के युवाओं को शासकीय भर्तियों में निष्पक्ष और पारदर्शिता से युक्त परीक्षा का वातावरण मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इससे भर्ती परीक्षाओं में न सिर्फ युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि परिश्रम से वह अपने सपनों की उड़ान को पूरी कर सकेंगे। सरकार के गठन के पहले महीने में ही विष्णु देव साय सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकमत आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर तथा अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

संवाद 40024/71

आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमपंथ पर ठोस प्रहार

छत्तीसगढ़ सरकार ने आतंकवाद, नक्सलवाद और चरमंथ को समूल नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर स्टेट इनवेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जा रहा है। यह एजेंसी आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी मामलों की प्रभावी और त्वरित जांच करेगी। इसके लिए एसआईए एनआईए के साथ समन्वय स्थापित करने वाली राज्य की नोडल एजेंसी होगी। नक्सल प्रभावित गांव के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी 2024 को नियद नेल्लानार योजना शुरु की गई है। इस योजना के जरिए सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में 24 योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा चुका है। पुलिस द्वारा नक्सल प्रभावित गांव में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं। सुकमा के पूवर्ती समेत अन्य स्थानों पर यह पुलिस कैंप कानून व्यवस्था को मजबूती देने के साथ सुशासन के प्रकल्प बनकर उभरे हैं।

भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब राज्य की नवनिर्वाचित सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का पहला डिजिटल बजट पेश किया। इससे शासन एवं प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे। राज्य में कोयले के परिवहन हेतु परमिट और स्वीकृति व्यवस्था मैन्युअल होने से पूर्व की सरकार के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। ऐसे में विष्णु देव साय सरकार ने तत्काल इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मिसाल पेश की है। प्रदेश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपये, पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपये, एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये और अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।

विगत 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में 'महतारी वंदन योजना' की पहले किस्त की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने माता- बहनों को शुभकामनाएं दीं।

'महतारी वंदन' योजना से हो रहा महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण विष्णु देव साय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के इतिहास में 12 मार्च 2024 की तारीख महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपये की पहली किश्त जारी की गई। विष्णु देव साय सरकार हर साल 12 हजार रुपये महिलाओं के खाते में जमा करेगी। भ्रष्टाचार के बिना हितग्राहियों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ डीबीटी का सबसे बेहतरीन उपयोग करने वाला राज्य बन चुका है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंगविभेद, असमानता खत्म करते हुए उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। विवाहित महिला के साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यकता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिल रहा है।

महतारी वंदन हेल्पलाइन- 0771-2220006 / 0771-6637711

किसानों के चेहरे पर खुशी... छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य

छत्तीसगढ़ में धान की फसल यहां के किसानों के लिए तरक्की का आधार है। विष्णु देव साय सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की मोदी की गारंटी को पूरा कर देश में किसानों को धान का सर्वाधिक समर्थन मूल्य देने का कीर्तिमान रच दिया है। किसानों के खाते में सीधे नगद लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए पैसा भेजा जा रहा है। खरीफ सीजन 2023 में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ (3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से) 147 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। इस तरह छत्तीसगढ़ ने देश में धान की खरीदी का रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य में 13 लाख किसानों के खाते में धान के दो वर्ष के बकाया बोनस के रूप में 3,716 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कृषक उन्नति योजना के जरिए किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि 13,320 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 24.72 लाख से अधिक किसान विष्णु देव साय सरकार की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

"अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @2047"

विजन डॉक्यूमेंट में राज्य हेतु संभावित विकास क्षेत्रों जैसे कि ईन्फास्ट्रक्चर विकास, कृषि आधुनीकीकरण, शिक्षा व कौशल विकास,GYAN आधारित विकास, निवेश को प्रोत्साहन, खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग, रिन्यूवेबल एनर्जी, कॉटेज इंडस्ट्री विकास, प्रभावी फिस्कल व टैक्स पॉलिसी व तकनीक का उपयोग, छोटे एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स, टूरिज्म विकास, स्वास्थ्य व पोषण, जनजाति विकास, ग्रामीण विकास, नगरीय विकास हेतु रणनीति व कार्ययोजना का समावेश होगा। जिसके आधार पर संबंधित विभाग अपने-अपने सेक्टर में अपेक्षित प्रगति प्राप्त कर विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना में महती भूमिका सुनिश्चित करेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
- डिग्री हासिल करने वाले 246 एमबीबीएस एवं 21 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति दे दी गई है। इनमें से पचास फीसदी की नियुक्ति बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए की गई है।
- स्वास्थ्य विभाग में 5 हजार से ज्यादा पदों पर पीएससी और व्यापम के जरिए भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
- एमबीबीएस एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर नियुक्ति देने की घोषणा की गई है।
- कोल परिवहन के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली - खनिज संसाधन से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली लागू की गई है।
- नियद नेल्लानार योजना (बस्तर के लिए) बस्तर संभाग के नक्सल पीड़ित क्षेत्र में स्थापित 14 नये कैंपों में नवाचार के रूप में इसके आसपास के 5 ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता की दृष्टि से अधोसंरचना विकास एवं परिवारों के सम्यक विकास की कार्यवाही की जाएगी।
- कॉलेज के विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना ट्रैवल एलाउंस अगले शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को 6000 रुपए सालाना ट्रैवल एलाउंस मिलेगा।
- संस्कृत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय शासकीय दूधाधारी श्री राजेश्री महंत वैष्णव दास स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का संकल्प।
- आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में इसी सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी।
- 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी अगले शिक्षा सत्र में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- सभी जिला मुख्यालयों में एम्स की तर्ज पर उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का निर्णय।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)